सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

05 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 05 जुलाई, 2019 ई0

त्रयोदश सत्र — 14 आषाढ़,1941(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्प-सूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, महोदय, ...

अध्यक्ष : आप समय पर उठाईयेगा न, अभी प्रश्न है ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, सूचना ग्रहण किया जाय सर .....

अध्यक्ष : ठीक है, आपकी सूचना हो गई । अल्पसूचित प्रश्न संख्या-5 । माननीय सदस्य श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-5 (श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

2. दिनांक 28.06.2019 तक आई0डी0एस0पी0, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ए0ई0एस0 से कुल 154 बच्चों की मृत्यु हुई है । मृत्यु दर में कमी वर्ष 2013 में 38 प्रतिशत मृत्यु दर थी जो वर्तमान में 21 प्रतिशत है ।

3. बिहार सरकार द्वारा ए0ई0एस0 मरीजों की चिकित्सा हेतु आदर्श क्रियान्वयन पद्धति (SOP) 2013 तैयार की गई थी, जिसे 2018 में पुनरीक्षित किया गया था, जिसे राज्य के सभी चिकित्सकों को उपलब्ध कराया गया है । वर्त्तमान में राज्य में 12 ए0ई0एस0 प्रभावित जिलों के 222 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय एवं सदर अस्पताल में आदर्श क्रियान्वयन पद्धति (SOP) 2018 में वर्णित आवश्यक उपकरणों एवं दवाईयों की उपलब्धता करा दी गई है । इस वर्ष संबंधित जिलों के 445 चिकित्सा पदाधिकारियों एवं 472 आयुष चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

राज्य के सात चिकित्सीय संस्थान यथा-जिला अस्पताल, मोतिहारी, हाजीपुर एवं अनुमंडलीय अस्पताल, रजौली, नवादा एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर, पी0एम0सी0एच0, पटना, डी0एम0सी0एच0, दरभंगा ए0एन0एम0सी0एच0, गया, गया के शिशु रोग विभाग में

भारत सरकार के मान के अनुरूप शिशु चिकित्सा हेतु दस शय्या आई0सी0यू0 की स्थापना हो चुकी है, जो पूरी तरह कार्यरत है । मरीजों को चिकित्सा संस्थान में लाने एवं वापस ले जाने हेतु निःशुल्क व्यवस्था की गई है । एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर के पी0आई0सी0यू0 में बेडों की संख्या बढ़ाकर 14 से 66 कर दी गई है । सरकार इस बीमारी के प्रति अत्यंत गम्भीर है और सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं । तथ्यात्मक है कि अभी तक राज्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थानों द्वारा ए0ई0एस0 के तहत बीमारी के कारणों के संबंध में ठोस कारकों का निर्धारण नहीं किया जा सका है ।

राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा पदस्थापित / प्रतिनियुक्त चिकित्सकों द्वारा लगातार सेवा दी जा रही है । इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है ।

इस वर्ष 28 जून तक कुल 720 मरीज आये जिसमें से 566 स्वस्थ हो कर गये । स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि 2013-14 में रू0 338/- था, जो 2018-19 में बढ़कर रू0 804/-हो गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उत्तर दिया हुआ है । माननीय सदस्य, आप पूरक पूछिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में खंड-3 में यह बताया है कि बिहार सरकार द्वारा ए0ई0एस0 मरीजों की चिकित्सा हेतु आदर्श क्रियान्वयन पद्धति (एस0ओ0पी0) 2013 तैयार की गई थी, जिसे 2018 में पुनरीक्षित किया गया और वर्तमान में राज्य में 12 ए0ई0एस0 प्रभावित जिलों के 222 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं सदर अस्पताल में आदर्श क्रियान्वयन पद्धति में वर्णित आवश्यक उपकरणों वगैरह की व्यवस्था की गई है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन अस्पतालों का इन्होंने जिक्र किया है तो उसमें क्या इन अस्पतालों में स्वीकृत बल के हिसाब से चिकित्सक हैं और क्या उन अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों की जो इन्होंने कहा कि व्यवस्था करनी है और उसके लिए पुनरीक्षित भी किया गया है तो क्या उन स्थानों पर आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की गई है ?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा ....

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इस्तीफा मांगा है.....

अध्यक्ष : तो जवाब कैसे सुनियेगा ?

(इस अवसर पर राजद के सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि एस0ओ0पी0 जो 2018 में बना, उस 2018 एस0ओ0पी0 के अनुसार सारी कार्रवाई की गई है और उसी में आगे भी कहा है कि 445 चिकित्सा पदाधिकारी एवं 472 आयुष चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है तो जितने चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया है, उसके बारे में भी महोदय मैंने जानकारी दी है और जो आवश्यक दवाईयां और उपकरण इन संस्थानों में उपलब्ध कराने थे, वह एस0ओ0पी0 के अनुसार कराये गये हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

(व्यवधान)

महोदय, मैं माननीय सदस्यों से कुछ अपील करना चाहता हूँ और माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ । राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सभी जो सम्मानित सदस्य हैं, मैं इन सदस्यों से एक प्रश्न पूछता हूँ कि पिछले एक महीने से यह बीमारी है और मेरी आवाज मीडिया के मित्र सुन रहे होंगे, एक भी सुझाव किसी माननीय सदस्य राजद के द्वारा राज्य की सरकार या मंत्री को दी गई कि बच्चों को जान बचाने के लिए सरकार को और कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए और कोई काम होता है तो राजद के कई माननीय सदस्य मुझे फोन करते हैं और मुझे अपनी बात बताते हैं और मुझे काम के बारे में बताते हैं लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी आयी महोदय, इतनी बड़ी घटना हुई, एक सुझाव राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नहीं दिया । महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी घटना हुई, पूरे अस्पताल के अन्दर ....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-2/शंभु/5.7.19/

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य ।

माननीय सदस्यगण, शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :

राष्ट्रीय जनता दल	-	60 मिनट
जनता दल युनाइटेड	-	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	41 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	19 मिनट
सी0पी0आइ0(एम0एल0)	-	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	02 मिनट
हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा	-	01 मिनट
निर्दलीय	-	03 मिनट

माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 347,98,69,44,000/- (तीन सौ सैंतालीस अरब अनठानवे करोड़ उनहत्तर लाख चौवालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानन्द सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । जो व्यापक हैं एवं जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्किी का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(मा0स0श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी सदन में अनुपस्थित)

श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटाई जाय।"

महोदय, देख लीजिए एक सचिवालय की भूल है 3047 लिखा हुआ है उसका सुधार करवा लिया जाय । मेरी पार्टी की ओर से जो नाम है उसमें से ये बोलेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन । ये भी नहीं हैं ।

(मा0स0श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन सदन में अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र कुमार ।

श्री सुरेन्द्र कुमार : महोदय, मैं सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्तुत मांग के विरूद्ध कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, वास्तविक शिक्षा का तात्पर्य है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो, मानव अपने पैर पर खड़ा होना सीखे । महोदय, शिक्षा एक सामाजिक व्यवस्था है जिस तरह से मनुष्य अपने तन को ढंकने के लिए वस्त्र धारण करता है वैसे ही शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज को एक पोशाक के रूप में उसको आवरण के रूप में रखना पड़ता है- परिवार हो या समाज हो अगर शिक्षित नहीं हो तो शायद उस समाज या परिवार में अनुशासन का कोई औचित्य नहीं रह जाता और आज देखने को अधिकांश यही मिलता है- उचित शिक्षा वही है जो साधारण व्यक्ति को भी जीवन संग्राम में समर्थ बना सके। जो मनुष्य में चरित्र बल और परहित की भावना ला सके, सिंह के समान साहस ला सके अर्थात् शिक्षा मानव को जीवन मार्ग में चलने का पूर्ण ज्ञान कराता है । साथ ही मानव में मानवता के सही मार्ग को दर्शाता है । मेरा मानना है कि Education is a type of tharmometer which measure the nature and cultures of society. अध्यक्ष महोदय, जो आज बिहार सरकार की शिक्षा नीति बनी है, हमलोग गांव-गवई से आते हैं और जितने भी माननीय विधायक 2 सौ कुछ हैं और ग्रामीण विधान सभा से आते हैं । हमारे विपक्ष के माननीय साथी बजट पर जो पक्ष में बोले हैं वह बराबर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं कि 15 साल पहले क्या था, आपके 15 साल के शासन में क्या था ? लेकिन मैं झलकाना चाहता हूँ कि जब 1990 में एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ कि उस समय आपके बजट की बात करते तो उस समय 1990 में पेट्रोल की कीमत 9 रू0 84 पैसा, डीजल का 4 रू0 8 पैसा और केरोसीन तेल का 2 रू0 25 पैसा तो स्वाभविक है कि डिभैल्युएशन हुआ है रूपया का तो बजट बढ़ेगा ही लेकिन बजट जिस हिसाब से राज्य सरकार ने बढ़ाया है क्या आम आदमी जो अंतिम पायदान पर रहनेवाले लोग हैं क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है ? आप प्राइमरी एजुकेशन देखिए गांव का, आप मीडिल एजुकेशन देखिए, आप हाईस्कूल का एजुकेशन देखिए, आप कॉलेज का एजुकेशन देखिए न तो वहां कोई व्यवस्था है, न वहां कोई क्वालिटी है, न क्वालिटीफुल

कोई टिचिंग स्टाइल है । जितने भी प्रोफेसर हैं उनकी सब्जेक्टवाइज कमी हो चुकी है तो फिर कौन सा बजट और कौन सा सुशासन और कौन सी शिक्षा नीति की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपको सदन में बताना चाहता हूँ कि 2009 से पहले पी0एच0इ0डी0 किये लोगों को यू0जी0सी0 मान्यता नहीं दे रही है और आज स्थिति यह है कि कोई रिसर्च करना नहीं चाहता, चाहे आर्ट्स का सब्जेक्ट हो या साइन्स का सब्जेक्ट हो । पहले गौरव माना जाता था बिहार में शिक्षा पद्धति को । पटना के साइन्स कॉलेज को देखा जाय, मुजप्फरपुर के एल0एस0कॉलेज और आर0बी0एस0 कॉलेज को देखा जाय, दरभंगा के सी0एम0साइन्स कॉलेज को देखा जाय, भागलपुर के टी0एन0बी0 कॉलेज को देखा जाय- आज स्थिति क्या है ? हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां सही एजुकेशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं । हम तो सलाह देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो प्राइमरी एजुकेशन का इन्होंने सिस्टम बनाया है आज यदि प्राइमरी एजुकेशन हमलोगों का सही होता तो क्वालिटीफुल स्टूडेंट हमारे बिहार से बाहर नहीं जाते और बिहार में ही अपने भविष्य का निर्माण करते । प्राइमरी स्कूल चले जाइये, मीडिल स्कूल में चले जाइये, केवल खिचड़ी- जो टीचर हैं वे टीचर प्रखंड से लेकर के जिला तक फाइल लेकर दौड़ते रहते हैं और बेचारे टीचर को पढ़ाने का मौका नहीं मिलता । पेड़ के नीचे भी पढ़ते हैं बहुत जगह । आप जाते होंगे माननीय सदस्य दरभंगा के हों या समस्तीपुर के हों जब आप हाजीपुर से भगवानपुर जाते होइयेगा तो एन0एच0 के पूरब साइड में तीन साल से वह भवन बनकर तैयार है, लेकिन ताला लगा हुआ है और उसमें कोई पठन-पाठन का कार्य नहीं होता है । उसके अलावे....

क्रमशः

टर्न-3/ज्योति/05-07-2019

क्रमशः

श्री सुरेन्द्र कुमार : उसके अलावे डबल इंजन में शायद रुपये की कमी हो गयी होगी । अध्यक्ष महोदय, शायद यही बिहार हमलोगों का रहा है, जिस धरती से रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शरत चन्द्र चट्टोपाध्याय, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामधारी सिंह दिनकर जैसे महापुरुष लेखक, कवि हुए थे और उनके जो चिंतन थे, उनके जो लेखन थे, हमलोग पढ़ते थे, आज वह कहाॅ चला गया ? वह बिहार का परिप्रेक्ष्य, शिक्षा पद्धति जिससे एक कमल निकलता था, तरह तरह के फुल निकलते थे, कवि के रुप में और लेखक के रुप में, आज नदारद है ? आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि कमल मुरझा रहा है । जानकी वल्लभ शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहाॅ से उत्पन्न होंगे, क्या अब वैसी पठन पाठन की व्यवस्था है 15 साल के सुशासन में ? आज लंगट सिंह महाविद्यालय में, अध्यक्ष महोदय, मैं अपना उदाहरण बताना चाहता हूँ

कि एल.एस.कॉलेज में आई.एस.सी. से लेकर एम.एस.सी. और बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर, यूनिवर्सिटी से हमलोग पी.एच.डी. किए केमिस्ट्री से । एल.एस. कॉलेज में एक एक फैकल्टी मे 15-15 टीचर्स हुए करते थ । आर.एस.ठाकुर जैसे लोग, टी.शर्मा जैसे लोग केमीस्ट्री का किताब लिखते थे । मोहम्मद निजामुद्दीन साहेब, हेड औफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे लेकिन जब एल.एस.कॉलेज के कैम्पस में जाईयेगा, बिहार यूनिवर्सिटी के कैम्पस में जाईयेगा तो लगता है कि 1990 से लेकर 2005 या 1990 से पहले जो शैक्षणिक व्यवस्था थी वहॉ पर, आज एकदम धाराशायी हो गयी है, चरमरा चुकी है । कहीं भी, कोई स्टूडेंट अपना भविष्य वहॉ नहीं देखता है और न ही ढूंढना चाहते हैं । स्टूडेंट पलायन कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : ललित जी, माननीय सदस्य अच्छा बोल रहे हैं, काम की बात बोल रहे हैं इसलिए आसन गौर से सुन रहा है ।

श्री सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूॅं और विश्वास के साथ कहना चाहता हूॅं कि 85 परसेंट गोंव गवंई के लोग और उनकी पीढ़ी, आज इतना बड़ा बजट बना है लेकिन वह अज्ञानी बनने के लिए मजबूर है । शिक्षा का मतलब होता दलित हो, पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, सवर्ण के लोग हों 85 परसेंट लोग जो गांव में होते हैं, संसाधन विहीन होते, वह शहरी परिवेश में नहीं अपने आप को ढालना या आने के लिए कोशिश करते । उनकी आर्थिक मजबूरी होती है लेकिन आज हाई स्कूल की स्थिति देखी जाय, कहॉ से उस तरह की व्यवस्था ला दी लोगों ने, आज विवश हैं अज्ञानी होने के लिए लोग वहॉ गांव में और सही मेरिट वहॉ पर दबाया जा रहा है हुजूर, और उतना ही नहीं मैं कहूॅंगा कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है अगर एक बच्चा अगर झोपड़ी में जन्म लेता, एक बच्चा महल में जन्म लेता अगर महल वाले बच्चे को, अगर गांव के परिवेश में रख दिया जाय, झोपड़ी वाले बच्चे को अगर अच्छे माहौल में रख दिया जाय तो अच्छे माहौल वाले बच्चे बहुत आगे अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं लेकिन माहौल जहॉ खराब है व्यवस्था ही नहीं है, वहॉ महल वाले बच्चे बेकार हो जायेंगे । कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो पीढ़ी है वह जिस तरह मिट्टी को कुम्हार पूरा गूथ करके अपने कला कौशल से तरह तरह की बर्तन बनाते उसी तरह हमारे बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, मिट्टी के समान है, उनको जिस तरह गूथियेगा जिस परिवेश में रखियेगा उसतरह का बर्तन तैयार होगा लेकिन जो सुशासन की सरकार है, इसकी कोई चिंता नहीं है । आज आप देख लीजिये गांव में टेंथ का जो स्टूडेंट है परीक्षा देते, सबसे ज्यादा फेल टेंथ के स्टूडेंट हैं, गांव में रहते वह सही रास्ता नहीं पकड़ते । आज वैसे वैसे लड़के पकड़ाते हैं चाहे शराब बंदी का मामला आया हो वह भी प्रभावित हो रहा है इससे

और शराब बंदी भी आपका फेल्योर है और वही टेंथ फेल स्टूडेंट इसतरह के काम में लगते हैं कि तत्काल हमको कुछ आमदनी का साधन हो जाय । जिसतरह हमारे सरकार में बैठे लोग चाहतें कि तत्काल लाभ मिल जाय, सत्ता किसी तरह प्राप्त हो जाय, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम बरकरार रहे 15 साल, चाहे पीछे दरवाजे से ही क्यों नहीं आवे इसलिए नैतिकता की बात है । शिक्षा उसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है जिसतरह भोजन जरुरी है । इसलिए इतना बड़ा बजट जो लाया गया है उस बजट में कहीं से कोई प्रोविजन गरीब गुरबा जो गांव के लोग हैं उनके शैक्षिक माहौल को सही ढंग से सुचारु ढंग से सुदृढ़ करने के लिए कहीं कोई व्यवव्स्था नहीं है और जो नियोजित टीचर है आज पॉच पॉच महीना, छः छः महीना पर उनका वेतन मिलता, समान वेतन नहीं मिलता जिसके कारण वे भी अपनी गुणवता के आधार पर जो शिक्षा प्रदान करना चाहिए, वह नहीं करते हैं यह मापदंड ये वर्तमान की सुशासन की सरकार का है । अध्यक्ष महोदय, हमारे औराई विधान सभा क्षेत्र में, औराई प्रखंड परिसर में राम जीवन उच्च विद्यालय है, माननीय मंत्री जी से कई बार मांग खुद कर चुका हूॅं कि उसको मोड्ल हाई स्कूल बनाया जाय। लंप सम आठ दस एकड़ उसमें प्रखंड परिसर के मीडिल में वह जमीन है और आज वह भवन पुराना 50 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो भवन बना वही भवन है, उसी में शिक्षण कार्य और पठन पााठन का कार्यक्रम होता है । दूसरा जितने भी नये भवन बने हैं वह अभी हैण्ड ओवर नहीं किया गया है । उसमें पठन पाठन का कार्यक्रम नहीं चलाया गया है । उपस्कर का जहॉ तक सवाल है वह भी सभी स्कूलों में मुहैय्या नहीं कराया गया है ।

श्री महबूब आलम : महोदय..

अध्यक्ष : आप हैं ! सदन शांति से चल रहा था तो हमको लग रहा था कि कि आप हैं ही नहीं ।

(व्यवधान)

महबूब जी जब बोलेंगे तो मंत्री जी सुनेंगे । महबूब जी, मंत्री जी शायर हैं वह पता है न आपको । शिक्षा विभाग सिर्फ उनका कोई शासन का विभाग नहीं है, शिक्षा उनकी पसंद है ।

श्री सुरेन्द्र कुमारः उपस्कर का जहां तक सवाल है उसमें बहुत बड़े गबन की भी बू आती है इसको भी विभागीय स्तर पर जॉच करवायी जाय । अध्यक्ष महोदय, ..

अध्यक्ष : अब सुरेन्द्र जी, अब एक दो मिनट में समाप्त कर दीजिये ।

श्री सुरेन्द्र कुमार : जी, और विपक्ष के साथी 15 साल का बड़ा दोहा पढ़ते हैं लेकिन बी.पी.एस.सी. के द्वारा हमको लगता है कि इस बिहार में पहली बार माननीय लालू प्रसाद यादव जी

का जब समय था तो बी.पी.एस.सी. से टीचर की जब बहाली हुई, आज आपके बिहार का प्राईमरी एजूकेशन हो, मिडिल एजूकेश्न हो, उसकी रीढ़ बची हुई तो माननीय लालू यादव जी द्वारा टीचर की जो बहाली बी.पी0.एस.सी. के द्वारा की गयी उसके कारण बची हुई है । मैं मांग करुंगा संजय भाई ..

अध्यक्ष : आप इधर देख कर बोलिये ।

श्री सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सलाह दूंगा कि फिर से वही परिपाटी अपनायी जाय और बी. पी.0एस.सी. के द्वारा टीचर की बहाली हो ताकि क्वालिटीफुल टीचर गांव से लेकर गंवई तक जाय और गरीब गुरबा के जितने भी बच्चे हैं, मैं नहीं कहता जातीय आधार पर सवर्णों के लोग भी गरीब लोग गांव में बसते, ऐसा नहीं है कि सवर्ण सभी धनी होते और 5 यूनिवर्सिटी लालू यादव जी ने स्थापित किया आप क्या किये ? हमको लगता है कि जो यूनिवर्सिटी बना वह चरमरा दिए वह भी सुसज्जित ढंग से नहीं बचा है इसलिए अध्यक्ष महोदय पर्यावरण से संबंधित कुछ मामला है क्षेत्र का ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री सुरेन्द्र कुमार : श्री मिथिलेश तिवारी जी नहीं है । मैं 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे समीक्षा बैठक में, मुजफ्फरपुर रीगा चीनी मिल का जहरीला पानी वर्षों से लखनदेई नदी में लोग गिराते हैं ।

क्रमशः

टर्न-4/05.07.2019/बिपिन

श्री सुरेन्द्र कुमार : क्रमशः .. उसका पत्रांक-दिनांक भी हम आपको मुहैय्या करा देंगे और वैसे मुख्यमंत्री जी का भी जवाब आया हुआ है और जब मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी जब गए तो उन्होंने प्रश्न उठाया पहला कि कमिटी बने और वहां जांच कर आवे । जांच में पाया गया कि लमसम दो कि0मी0 रीगा चीनी मिल अनअथॉराइज-वे में पाइप लाइन लखनदई नदी में गिराया हुआ है अध्यक्ष महोदय और वह जो गंदा और जहरीला पानी लखनदेई में गिरता है, मवेशी उसको स्पर्श करता है तो उसको घाव हो जाता है, बच्चे जब हेलते हैं उसको फफोला हो जाता है । तरह- तरह की बीमारियां हो जाती हैं । हजारों एकड़ जमीन रीगा से लेकर रून्नी सैदपुर, औराई और कटरा होकर जब लखनदेई गुजरती है तो हजारों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है ।

अध्यक्ष : आप शिक्षा पर बोल रहे थे ।

श्री सुरेन्द्र कुमार: पर्यावरण पर भी था महोदय । तो अध्यक्ष महोदय, रूक गया था लेकिन किस कारण से फिर वह चालु हो गया ? कभी-कभी बागमती नदी....

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए ।

श्री सुरेन्द्र कुमार: इसीलिए अध्यक्ष महोदय, इसपर थोड़ा-सा पहल करवाया जाए । इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री अचमित ऋषिदेव ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार और अपने दल के नेताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा । मैं अनुदान के मांग पर सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

(व्यवधान)

महोदय, अनुदान के मांग पर सरकार के पक्ष में बोलने का अवसर मिला है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के महत्व को हमलोग जानते हैं । शिक्षा लोगों के स्तर को निर्धारित करती है । शिक्षा विभाग के माध्यम से बिहार में साक्षरता दर में सुधार हुआ है और सुधार करने के लिए लगातार काम कर रही है । गुणवत्ता के साथ शिक्षा में सौ प्रतिशत साक्षर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग बिहार में विभिन्न योजना और कार्य करने की शुरूआत की है ।

महोदय, बिहार में 2005 में लगभग 12.5 प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर थे। बच्चे को विद्यालय में लाने के लिए राज्य में अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसका सुखद परिणाम हमलोगों के सामने में है । आज बिहार में 99 प्रतिशत बच्चे स्कूल में नामांकित हैं। शेष एक प्रतिशत बच्चों का विद्यालय में लाने के लिए नवाचार नियुक्त कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । महोदय, निकट भविष्य में राज्य का शत्-प्रतिशत् बच्चे इसके लिए एक किलोमीटर के दायरे में 21,264 नए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई है । तीन किलोमीटर के पर मध्य विद्यालय के लिए 19625 प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है । सभी विद्यालय में पेयजल की सुविधा की गई है । राज्य के 3520 पंचायतों में मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है । विद्यालय में शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे । अनुश्रवण के लिए बी.इ.एस.टी. नामक एप का निर्माण किया गया है । महोदय, अब प्राथमिक विद्यालय में अनुश्रवण की जा चुकी है । महोदय, राज्य में बालिका शिक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं । साईकिल योजना, पोषाक योजना, छात्रवृति योजना आदि से बालिका के शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है ।

(इस अवसर पर डॉ0 अशोक कुमार ने माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया ।)

सभापति महोदय, आज माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिका शिक्षा में प्रगति हुई है । मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना अंतर्गत कक्षा-9 में बालिका नामांकित

5,15,960 छात्रों के लिए प्रति छात्र तीन हजार की दर से राशि उपलब्ध कराया गया है । इसके लिए कुल 154.7 करोड़ रूपया जिला में आवंटित किया गया है । महोदय, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना अंतर्गत कक्षा 9 में नामांकित कुल 4,59,625 छात्रों के लिए प्रति छात्र तीन हजार रूपए की दर से 137.89 करोड़ रूपया जिला में आवंटित किया गया है जिसमें अभी तक कुल 3,54,435 की राशि उपलब्ध करा दी गई गई । महोदय, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना की राशि एक हजार से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2018-19 से एक 1500 रूपए देने का प्रावधान किया गया है । इसके तहत 11,,56,587 छात्रों के लिए 173. 49 करोड़ रूपया जिलों को आवंटित किया गया है । महोदय, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सैनिटरी नैपकीन की राशि को 150 रूपया वित्तीय वर्ष 2018-18 से बढ़ाकर 300 रूपए कर दिया गया है । इसके तहत 18,73,000/-रूपया 434 छात्रों के लिए 56.2 करोड़ रूपया जिला में आवंटित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्ग एक से 12 तक नामांकित सभी बालिकों को दो सौ रूपए की दर से दस माह के लिए कुल 2000 रूपए दिए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । महोदय, सरकार के इन प्रयासों से बालिका शिक्षा में वृद्धि हुई है और राज्य में सभी बच्चियों पढ़ रही है । इससे कम उम्र में लड़कियों की शादी पर अपने आप रोक लग गया है । समाज में बदलाव आ गया है । सामाजिक परिवर्तन हो चुका है । इन बातों का सुखद परिणाम आने वाले समय में हमलोगों को दिखाई देगा । इससे प्रजनन दर में कमी आएगी । बढ़ती जनसंख्या निर्धारण से राज्य में सुलह आ गई है । राज्य में बाल विवाह पर अंकुश लगाने से कुल प्रजनन दर में कमी लाने एवं के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या योजना शुरूआत किया गया है । इसके तहत 2018-19 में इंटर में उत्तीर्ण प्राप्त सभी कोटि के विवाहित छात्रों को प्रति छात्र 10000 की राशि उपलब्ध करा दी गई है । महोदय, कुल 249.806 करोड़ रूपया जिलों में आबंटित किया गया है । बालिका के उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन के लिए राज्य में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन किया गया है । महोदय, सरकार ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बालिकाओं को प्रति छात्र 25 हजार रूपया देने का निर्णय लिया है । अभी तक दो सौ छात्रों को यह राशि उपलब्ध करा दी गई है । महोदय राज्य में शिक्षक के नियोजन में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है इससे महिला शिक्षकों की संख्या राज्य में 19 परसेंट से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया है । राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालय में 25 हजार प्रति माह के दर से गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के लिए चार हजार शिक्षकों की सेवा के लिए व्यवस्था की गई है । महोदय, राज्य में पहली बार इंटर स्तर पर ऑनलाइन नामांकन प्रारंभ किया गया है । इसके तहत लगभग 4 लाख 62 हजार छात्रों ने राज्य में 10 विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय एवं सबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय में नामांकन लिया गया है .. क्रमशः ...

टर्न : 05/कृष्ण/05.07.2019

श्री अचमित ऋषिदेव (क्रमशः) महोदय, राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं । प्रत्येक मंडल में एक-एक विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से बिहार राज्य विश्वविद्यलय अधिनियम,1976 में संशोधन किया गया है । इसके बाद मुंगेर विश्वविद्यालय एवं पूर्णियां विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है । इसके साथ ही पटना में पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, एक मिनट । राज्य में उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य से बिहार में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये निजी विश्वविद्यालय स्थापना अधिनियम,2013 में संशाधन किया गया है, जिसके तहत राज्य में 6 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसमें अमेटी विश्वविद्यालय पटना, के0 के0 विश्वविद्यालय, बिहारशरीफ, डा0 सी0 पी0 रमण विश्वविद्यालय आदि की स्थापना की गयी है ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार):अब आप समाप्त करें ।आपका समय समाप्त हो गया । श्री अशोक कु0 सिंह ।

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महोदय, विपक्ष द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके विरोध में और सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, शिक्षा के महत्व के संबंध में हम सभी माननीय सदस्य जानते हैं, इसमें बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : आप के पास 15 मिनट है ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि चाणक्य ने कहा था कि अगर आप एक साल तक सुखी रहना चाहते हैं तो धान और गेहूं की खेती कीजिये और 20 साल सुखी रहना चाहते हैं तो बगीचा लगाये और आप आजीवन सुखी रहना चाहते हैं तो अपने औलाद को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिये । यह महत्व है शिक्षा का सभापति महोदय। विकास का कोई भी रास्ता शिक्षा से ही होकर जाता है चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो । चाहे हम अपने बच्चों में नैतिकता भरें, चाहे हमारा समाज नैतिक हो मात्र एक ही रास्ता है और वह है शिक्षा, जिस रास्ते से हम विकास कर सकते हैं । महोदय, जब झारखंड बिहार से बंटा था चारे तरफ से एक ही आवाज आ रही थी कि अब बिहार के पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बालू ही बचा है । लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को जिन्होंने कहा कि हमारे 10 करोड़ बिहारवासियों के 20 करोड़ हाथ हैं, हम मानव संसाधन के बल पर हम बिहार का विकास करेंगे और राज्य को सबसे ज्यादा विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करेंगे और कहा ही नहीं बल्कि किया । सभापति महोदय, जिस

तरह के काम एन0डी0ए0 की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किया है, बच्चा हमारा हो, आपका हो, किसी का हो, जिस दिन बच्चा स्कूल जाने के लायक होता है सरकार उस के लिये पोशाक का इंतजाम करती है, उसके लिये जूते का इंतजाम करती है, उसके लिये पुस्तक का इंतजाम करती है ।

महोदयय,नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं । अगर सही माने में इनलोगों को शिक्षा में कितनी रूचि है, महोदय, ये लोग तो चरवाहा विद्यालय खोलनेवाले हैं । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष रहते, शिक्षा के क्षेत्र में एन0डी0ए0 की सरकार ने जितनी योजनायें चलायी है, शायद वह गिना नहीं पायेंगे कि कितनी योजनायें शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार चला रही है । सभापति महोदय, एक से एक योजना है ।

(व्यवधान)

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : आप जारी रखिये । ललित जी आप बैठ जाईये ।

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैंने 1981 में रामगढ़ हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया था, मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं,, वहां छात्र एवं छात्राओं की संख्या 950 थी, जिसमें छात्राओं की संख्या मात्र 27 थी । आज जितने छात्रों की संख्या है विद्यालयों में उससे अधिक संख्या छात्राओं की है । इसके लिये विपक्ष को एन0डी0ए0 की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए ।

महोदय, उस बिहार में घरों से बेटियां बाहर नहीं निकलती थी । जब हमारे हाई स्कूल की छुट्टी होती है और हमारे प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर 5 से 10 मिनट के अंतर पर हमारे बच्चियों और बच्चों को छोड़ते हैं, पहले बच्चियों को छोड़ते हैं और जब हमारी बच्चियां साईकिल चलाते हुये विद्यालय से निकलती है तो नहीं लगता है कि हम गांव में है, वह किसी शहर से कम महसूस नहीं होता है और हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम आगे जा रहे हैं ।

महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अविवाहित इंटर पास छात्राओं को 10 हजार रूपये दिये, ग्रेजुएट के लिये भी निर्धारित है, जब तक हमारी बेटियां नहीं पढ़ेगी, शिक्षित नहीं होगी तबतक जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हो सकता । महोदय, आज शिक्षा का ही तो फल है, आज जागरूकता का ही तो फल है कि 40 में हम 39 हैं और ये लोाग एक है चरवाहा विद्यालय खोलनेवाले । ये नहीं चाहते कि राज्य के बच्चे और बच्चियां पढ़ें, समझदार हों और अपनी समझ से निर्णय लें । महोदय, जिस दिन समय से फैसेला होगा, ये जीरो पर आऊट होंगे । इसलिये इनको कोई चिन्ता नहीं है ।

सभापति महोदय, दूसरी बात है कि सरकार ने संकल्प लिया है कि जिस तरह से हमारे छात्र एवं छात्राओं की संख्या बढ़ रही है, जो हमारे पुराने विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें एक-एक विद्यालय में एक-एक हजार छात्र-छात्राओं का नामांकन हो

रहा है लेकिन सरकार ने संकल्प लिया है कि हम हर पंचायत में उच्च विद्यालय बनायेंगे, पंचायत से बाहर हमारे बच्चे और बच्चियों को हाई स्कूल पास करने के लिये नहीं जाना पड़ेगा । माननीय सदस्य श्री शक्ति भाई, इसके लिये आप को धन्यवाद देना चाहिए सरकार को नहीं तो यदि श्री नीतीश कुमार और श्री सुशील कुमार मोदी जी नहीं होते तो आप अपने मतदाताओं के बेटे-बेटियों का विद्यालय में नाम नहीं लिखवा पाते और आप को क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ता । महोदय, सरकार ने फैसला लिया है कि शिक्षकों के जो पद खाली हैं चाहे माध्यमिक और इन्टर का हो, प्रक्रिया में हैं और उन पदों पर जल्द से जल्द शिक्षकों को बहाल करेंगे और सभी विद्यालयों को शिक्षक उपलब्ध करायेंगे ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बिहार की सरकार ने इस साल जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, माध्यमिक और इंटर का परिणाम 28 दिनों के अंदर घोषित किया। सभापति महोदय, देश के किसी राज्य ने यह नहीं किया है, जो हमारे राज्य की सरकार ने किया, 28 दिनों के अंदर परिणाम घोषित कर दिया और देश के किसी राज्य की सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है ।

महोदय, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, गरीब आदमी कभी यह सोचता नहीं था कि हमारा बेटा इन्जीनियर बनेगा, डाक्टर बनेगा, आई0पी0ए0 और आई0 ए0 एस0 बनेगा, लैप टॉप चलायेगा ।

क्रमशः

टर्न-6/अंजनी/दि0 05.07.19

श्री अशोक कुमार सिंह : क्रमशः..... जिन्होंने संकल्प लिया कि राज्य के किसी भी गरीब का बेटा और बेटी अगर होनहार है, पढ़ना चाहता है, आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी पढ़ाई पैसे के अभाव में बाधित नहीं होगी, सरकार ने स्वयं निगम बनाकर ऋण देने का काम किया है । सभापति महोदय, इस तरह का काम...

(व्यवधान)

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : अशोक जी, आप अपना भाषण जारी रखिए ।

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महोदय, हाउस को औौर्डर में लाया जाय, आपका संरक्षण चाहिए। सत्य सुनिए ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए । सरावगी जी, आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं । बोलिए ।

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महोदय, राज्य का कोई भी होनहार छात्र हो या छात्रा, अगर यू0पी0एस0सी0 फेस करता है तो उसको कोचिंग करने के लिए सरकार तुरंत 1 लाख 50 हजार रूपया शहर में पढ़ाई करने के लिए और आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 बनने का मौका दे रही है । तो यह सोच इनके अन्दर नहीं है, सोच तो उसी के अन्दर हो सकती है जो गरीबी को देखा हो, गरीबी के विषय में जानता हो और गरीबों से प्यार करता हो, वही आदमी इस तरह की बात सोचकर इस तरह की योजना चला सकता है तो वह सोच आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास है और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के पास है, इन लोगों के पास नहीं है । सभापति महोदय, हर क्षेत्र में चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा के हर क्षेत्र में सरकार अनुकरणीय कार्य कर रही है । सरकार ने संकल्प लिया कि हम बिहार में शराबबंदी बंद करेंगे, शराब को बंद करेंगे और जिस तरह का रोल, जिस तरह की भूमिका शिक्षा विभाग ने शराबबंदी में निभायी है, बच्चों ने अपने अभिभावकों से कहा कि पापा शराब मत पीजिए और आज उसका परिणाम है कि घर का कलह समाप्त हुआ, दुर्घटनायें समाप्त हुई और शांति से हमारे बेटा और बेटी पढ़ाई कर रहे हैं और शराब बिहार में बंद हो रही है । उसी तरह का अभियान हमारी सरकार ने चलाया बाल विवाह को रोकने के लिए, उसमें भी हमारे माननीय मंत्री आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे, उसमें भी भारी सफलता सरकार को मिली है । यही नहीं, जो हमारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उसको तो सरकार आगे बढ़ा ही रही है । राज्य में सात सरकारी महाविद्यालय हैं, उनको भी आगे ले जाने के लिए सरकार अपने नियम और कानून को शिथिल करके सरल बनाकर आगे ले जाने का काम कर रही है । हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी सरकार कर रही है, राज्य के 12 जिलों में अबतक खुल चुका है, तो इस तरह का काम हमारी सरकार कर रही है। हम आग्रह करेंगे कि अपने विपक्ष के साथियों से कि यह जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है, हमारी और आपकी भी जिम्मेवारी है । हमलोग सभी उच्च विद्यालयों के अध्यक्ष हैं और यह मामूली बात नहीं है, सरकार ने हमें जिम्मेवारी सौंपी है, इस जिम्मेवारी का निर्वहन अगर हम ठीक से करें, जागरूक होकर करें और छात्र और छात्राओं के अभिभावक को जागरूक करें तो जिस तरह का संसाधन राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है, उस संसाधन से निश्चित रूप से हम बिहार को आगे ले जायेंगे । किसी भी कीमत पर कोई हमें आगे जाने से रोक नहीं सकता है सभापति महोदय लेकिन इसके लिए रूचि लेनी होगी हमको, आपको, सबको । हम आपको कोई शिक्षा नहीं दे रहे है लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेवारी है । मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, हमारे यहां जो विद्यालय है, सरकारी विद्यालय हैं लेकिन उन विद्यालयों में बस चलती है, हमारी छात्रायें बसों से घर आती है और बस चलाने का जो

फीस होता है, उसको हमारे अभिभावक अदा करते हैं और शान से, प्रतिष्ठा से हमारी बेटियां घर से विद्यालय बस से आती है और विद्यालय से घर बस से जाती हैं । इस तरह की व्यवस्था हो रही है । सभापति महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को कि सरकार ने बहुत काम किया है लेकिन कुछ गांव हमारे क्षेत्र में या चाहे सभी माननीयों के क्षेत्र में छूट गये हों जो शुद्ध रूप से गरीबों के गांव है, गरीबों का टोला है, जहां आजतक प्राथमिक विद्यालय नहीं है ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : आप कनकलुड कीजिए, समाप्त कीजिए ।

श्री अशोक कुमार सिंह : नियम है कि भारत सरकार देगी तो बिहार सरकार बनायेगी । भारत सरकार से..

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री अशोक कुमार सिंह : बिहार सरकार मांग करे नहीं तो अपने मद से जो टोला छूट गये हैं, जहां के बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर, जी0टी0 रोड पार करना पड़ता है, रेलवे लाईन पार करना पड़ता है, जिसके कारण बच्चा पढाई से वंचित हो रहे हैं । हमारे दुर्गावती प्रखंड में मैरे गांव है, एक सारणपुर गांव है । दुर्गावती प्रखंड में मैरे, सारणपुर विंद टोला, नावानगर विंद टोला, श्रीरामपुर डेरा विंद टोला और बुनियादी विद्यालयों की स्थिति को सुधारे, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य शकील अहमद खॉं ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : सभापति महोदय.......

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : अवधेश बाबू आप ही के दल के सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री बैठे हैं, गया जिला में शिक्षक शराब पीकर स्कूल में गये और उनपर एफ.आई.आर. भी हुआ....

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य को क्या हो गया है, अगर कोई माननीय सदस्य सदन में अपनी बात रख रहे हैं, अगर सरकार का उत्तर होता है, टोका-टोकी होता है तो बात समझ में आती है लेकिन ये विपक्ष के माननीय सदस्य, अगर कोई माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं, उनकी जानकारी में जो बातें हैं, वे रखते हैं और अवधेश बाबू जैसे सीनियर मोस्ट मेम्बर इस सदन के, वे हर दिन कुछ-न-कुछ ऐसे सवाल उठाते है तो आपके पार्टी का समय पर्याप्त है, जितना चाहिए, उतना बोलिए और अकेले बोलना चाहिए तो आपको कौन रोकेगा । इसलिए सारा पार्टी का समय अवधेश बाबू को दे दिया जाय ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खॉं, आप बोलिए, आपका समय 19 मिनट है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य को बोलने दीजिए ।

श्री शकील अहमद खां : सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । (व्यवधान) आप जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ ।

शिक्षा के सवाल पर इस इजलास के प्रजेंस, मुझे लगता है कि इस बात की रमाजी करते हैं कि हम शिक्षा को लेकर कितने सीरियस हैं । शिक्षा जैसे सब्जेक्ट, इल्म और हुनर विजडम प्राप्त करने के सब्जेक्ट पर हमें बहुत ही संजीदगी से सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे वजीर शेरो-शायरी पसंद करते हैं, इसलिए कि वे समझते हैं । जो सुरते-हाल बिहार में और हिन्दुस्तान में शिक्षा की हो रही है और जिस तरह से पैसों की कमी की वजह से हिन्दुस्तान में अब बेहतरीन शिक्षा कम लोगों के पास रह जायेगी और अधिकांश जनसंख्या बेहतरीन शिक्षा से वंचित हो जायेगी ।

...क्रमशः....

टर्न-7/राजेश/5.7.19

श्री शकील अहमद खॉं, क्रमशः और अधिकांश जनसंख्या बेहतरी शिक्षा से वंचित हो जायेगी, इसलिए एक शेर है इकबाल का, मंत्री महोदय सुनें, आपको यह पसंद आयेगा, यह इकबाल का शेर है लेकिन यह आजादी के संदर्भ में यह बातें कहीं थी कि:

''वतन की फिक्र कर नादॉं, मुसीबत आने वाली है,
तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में,
न समझोगे तो मिट जाओगे हिन्दुस्तॉं वालों,
तुम्हारी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में ।''

जो पहला लफ्ज इल्म के ताल्लुक से वेद हो पुराण हो, शिक्षाविद हो, दुनियॉं जब से बनी है और जब तक बनी रहेगी लाखों साल पहले की दुनियॉं से ले करके आज तक शिक्षा और विजडम के उपर हमेशा मेहनत होगी जो पहला लफ्ज प्रोफेट मोहम्मद साहब के कान में पड़ा, सब लोग जानते हैं समझते हैं, जुब्राईल ने जो पहला लफ्ज कहा वो एकरार था पढ़, पढ़ने का शब्द आया, यह पहला लफ्ज था, इसके इम्पौरटेंस को समझिए, अरबी में एक आयत है तालबे इल्म फरिजैम, अल्लाहकुलम मुस्लिम मुसमात, कि हर मर्द औरत पर इल्म फर्ज है, यह शिक्षा को ले करके हम सब लोग इस बात को जानते हैं हम बचपन में विद्याधन उधम बिना कहो कि पावे कौन, हमेशा पढ़ते थे, 'बिना

डोलाये न डुले जैसे पंका पौर' । अभी चाणक्य का भी जिक्र किया, हमारे एक साथी ने चाणक्य ने यह भी कहा है कि दूर दराज इलाकों में जब भी तुम रहो, तो तुम्हारा सबसे बेहतरीन साथी शिक्षा ही है, यह तो उसकी जरुरत और हिफाजियत की ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इस इजलास में जितने भी लोग मौजूद हैं, अधिकांश लोग अपने जीवन काल में अपने–अपने जमाने में मिडिल स्कूल, हाईस्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जिन माध्यम से पढ़कर आये हैं, वह माध्यम पिछले 30 साल पहले ले जाना चाहता हूँ । मा0 सदस्य तारकिशोर जी यहाँ मौजूद है, ये कटिहार जिला को जानते हैं, मैं उस गाँव में पढ़ता था सातवीं जमात तक का स्कूल था और उस वक्त वहाँ पर 12 टीचर थे लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि आज कितने हैं, उसके बाद आठवीं जमात के बाद 11वीं जमात तक जो हाईस्कूल था, कोई ऐसा सबजेक्ट नहीं था कि जिसके टीचर वहाँ एभेलेबुल नहीं थे और बढ़िया तालीम नहीं दे रहे थे, आज का फीगर आपको पता है कि क्या है ? कटिहार जिले में 112 उत्क्रमित हाईस्कूल में सिर्फ 114 टीचर है 'दिस इज द सिचुएशन' । यह तो सबके लिए है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि संजीदगी से इन सब बातों पर गौर करना चाहिए, कॉलेज में आई0ए0सी0 हमने पूर्णिया कॉलेज से किया, कोई ऐसा सबजेक्ट नहीं था जिसके टीचर वहाँ एभेलेबुल नहीं थे, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में, मैं आर्ट्स में चला आया, सुशाल जी हो, अमरेश जी हो, उर्दू जुबान तीनों सबजेक्ट में टीचरों की कमी नहीं थी, यह जमाना 1988 तक का था, बजट प्रोविजन कम थे, आज बजटरी प्रोविजन 17.1 प्रतिशत है आपका, दो लाख करोड़ का बजट है लेकिन इच्छाशक्ति पिछले 28, 29 सालों से और यह कोई पक्ष और विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, माफ कीजियेगा, 1988 की सिचुएशन को मैं बता रहा हूँ, बजटरी प्रोविजन कम थे, पैसे कम थे लेकिन स्कूल टीचर की गुणवत्ता, स्कूल टीचर के हालात और स्टुडेंट जो पढ़ता था, उसके गुणवत्ता के बारे में आप और हम सभी जानते हैं, इसलिए की इच्छाशक्ति थी, जो पोलिटिकल अन्डरस्टैंडिंग थीं कि सेहत और तालीम हियूमेन इनडेक्स में इम्पौरटेंट रॉल प्ले करते हैं और इसीलिए उसपर महत्ता दी गयी थी, हमारे प्रॉयरिटिज अलग थे लेकिन 1990 के बाद यह सही है कि सोशल इम्पावरमेंट का चला और चलना चाहिए और यह सही है सोशल इम्पावरमेंट में, पोलिटिकल इम्पावरमेंट, आर्थिक रुप में इम्पावरमेंट होना चाहिए लेकिन एडुकेशन इम्पावरमेंट किये बिना, सेहत का इम्पावरमेंट किये बिना वह वंचित समाज, वह दलित समाज, वह पिछड़ा समाज वो बिलो प्रोभर्टी लाईन का समाज जिसको हम बेहतरीन तालीम से रुसनात नहीं कराया तो सिचुएशन क्या होगी ? इसका मतलब क्या हुआ, यह बात सही कहा 1994 में बी0पी0एस0सी0 के द्वारा हाईस्कूल में जितने टीचर बहाल किये गये, वह एक बेहतरी मिशाल थी, मैं कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ

लेकिन 2005 के बाद ऑलमोस्ट एन0डी0ए0 की सरकार रही, उसके बेहतरी कामों में यह काम जरुर रहा कि बच्चियों के तालीम की तरफ बेहतरीन कदम उठाये गये लेकिन उस वक्त बजटरी प्रोविजन आप याद कीजिये 2004 से 2014 तक यू0पी0ए0 की सरकार थी, राज्यों के शिक्षकों का ऑकड़ा, राज्य का जो बजट था, वह कैसे बढ़ा तो उसमें उस प्रोविजन को माना गया कि काम किया गया है, तो इसीजिए बहुत ही संजीदगी के साथ इस बात को सोचना चाहिए कि 28 साल के पिरिएड में आज जो पोजिशन हैं, डी0एस0 कॉलेज कटिहार में तारकेश्वर बाबू यह बात मैं फिर आपको कह रहा हूँ, वहॉ पर 92 टीचर थे, तारकिशोर बाबू हमारे बड़े भाई हैं, वे जानते हैं, वे भी उसी कॉलेज से पढ़े हैं, 92 टीचर थे डी0एस0 कॉलेज में, तमाम सबजेक्ट के टीचर थे, तो कौन सी पौलिटिक्स थी आपकी, लास्ट 28 इयर्स, मैं तो कॉग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, आप इस बात को जानते हैं, वे कौन लोग थे, जो घटते-घटते आज 22 के तादाद पर है और आप कहते हैं कि बिहार की शिक्षा बहुत ही अच्छी है, आज हम आठवीं जमात तक यह कह सकते हैं, यहॉ पर ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे हैं, मैं मानता हूँ कि प्राईमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में टीचरों की बहाली हुई लेकिन यह कैसी हुई, आप जानते हैं, अगर इसपर बहस हो, तो लंबी बहस हो जायेगी, उसमें गुणवत्ता का किसतरह से ख्याल रखा गया है, आप हम सब जानते हैं, उसमें क्वालिटी एडुकेशन का ख्याल किसतरह से रखा गया है, आप सब जानते हैं, इसपर बोलने की जरुरत नहीं है । जब वह बहालियॉ हो रही थीं, तो क्या आपने उस समय ऑब्जेक्शन किया था कि इसमें यह प्यूरिटी होनी चाहिए, इसीलिए मेरे भाई हमको और आपको यह सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, यह बात सही है कि प्राईमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में टीचर आज हैं, 10 परसेंट की कमी हो सकती है लेकिन उसके बाद-क्वेश्चन ऑनसर करना है तो...............(व्यवधान)

मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ऑख खोलने की बात है मंत्री महोदय । 1990 में मैं था जे0एन0यू0 में, 1988 तक का कहानी बता दिया कि क्या सिचुएशन थी, महोदय 1988 के बाद मैं गया हुजूर, उससे पहले बचपना यही गुजरा, शिक्षा नीति यहीं मैं जानता हूँ । जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिये, तो मैं मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्राईमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में जो सिचुएशन बदली है,बच्चियों के तालीम के सिलसिले में जो मेहनतें हुई हैं, उस काउज और कोशिश से इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन 'नाईन्थ क्लास ऑन वर्ड्स'- आप चले जाइये बिहार का ब्रेन डेनर, मनी ड्रेन, फायनेंस ड्रेन होता है कि नहीं होता है, इसलिए कि टीचर्स नहीं हैं । बार-बार हमलोगों ने क्वेश्चन किया, यहां सदन के लोगों ने क्वेश्चन उठाया है टीचर्स की अवेबिलिटी के बारे में, बार-बार यह कह दिया जाता है कि अब हो जायेगा, कल हो जायेगा, परसों हो जायेगा । क्या यह हमारे लिये शर्म का विषय नहीं है, क्या यह हमारे

लिये संजीदगी का विषय नहीं है ? इसीलिए मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कहना चाहता हूँ । मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह इम्पोर्टेंट है । उसके बाद हमारे पक्ष के भाइयों ने अभी कुछ सिचुएशन हमारे सामने रखा, अच्छी बात है, 17 प्रतिशत आपका बजट तो है, लेकिन पूरे देश में आपका स्थान, पर-कैपिटा प्रति व्यक्ति जो साल में शिक्षा पर खर्च है, वह बिहार का लोयेस्ट है, तीसरा है । लोयेस्ट स्थान पर है आप क्या इसका जवाब देंगे लोयेस्ट है, ये आंकड़े हैं । यह गलत बात नहीं है यह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के आंकड़े हैं, पढ़ लिखकर आये हुए हैं आप, तो आपका पर-कैपिटा, एक इंसान पर साल भर में जो खर्च होना चाहिए, सेहत पर तो और भी कम है, सेहत पर तो 4 परसेंट है, आयेगा डिबेट तो मंगल पांडे जी को पकड़ूंगा ।

...क्रमशः...

टर्न-8/सत्येन्द्र/5-7-19

श्री शकील अहमद खां (क्रमशः): तो कहने का मतलब है कि अगर 300 जो हमारे पास आंकड़ा है उस लिहाज से आपका लोयेस्ट परकैपिटा खर्च आप कर रहे हैं और कहते हैं कि यह प्रायोरिटी सेक्टर में है । आपके प्रायोरिटी सेक्टर में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क पुल पुलिया बने, इससे इंकार नहीं है लेकिन आप समाज के सेहत और तालिम पर ख्याल अगर आप पहले नहीं करेंगे तो इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर नाम नहीं होगा इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ और अब हमारी फिर से एक नई शिक्षा नीति आयी है । आप अगर आंकड़े को देखेंगे तो आपको हैरानी होगी । पहली हमारी शिक्षा नीति 1968 में आती है फिर हमारी दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आती है और फिर आर0टी0ई0 जिसमें सभी लोग को 01-14 साल के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, कंप्लसरी शिक्षा है, ये जो सारे कानून बनाये गये हैं तो कोशिशें जारी है लेकिन कोशिशों में सेंसेटिभिटी इम्पौर्टेंट है, कोशिशों में आपकी प्रायोरिटी महत्वपूर्ण है वह है नहीं बिहार में, हमें वह कहीं भी नजर नहीं आता है इसलिए जरूरत इस बात की है, मैं सजेशन के तौर पर जो सजेशन दूंगा, उसका आप ख्याल करेंगे । आपको यहां पर जो डिबेट हुई, आपको बड़ा अजीव लगेगा, आप सबलोग चरवाहा विद्यालय के खिलाफ हैं, आप डिबेट कीजिये फिर इस पर आपको प्यांट बाईज यह बतलाना पड़ेगा, चरवाहा विद्यालय फेल हो गया, वह एक एक्सपेरिमेंट मैं मान सकता हूँ लेकिन आप ये बतलायें कि उस विद्यालय से उसके कंसेप्ट से लोगों को, गरीब लोगों को कहीं भी पढ़ा दिया जाय इससे फायदा हुआ कि नहीं, एडल्ट एजुकेशन जो एक शुरूआत था, आप हर चीज के लिए दोष मत दीजिये प्वायंट बाईज बतलाई कि उससे क्या नुकसान और क्या फायदा है । आप जब शिक्षा पर बात करते हैं तो आपको सिरियसली सोचना चाहिए कि किसी भी सरकार ने कोई नया

चीज लाया है तो उसके पीछे क्या फिलौस्फी है, वह फेल हो सकता है, पास हो सकता है लेकिन उस जरूरत को उस नफाजियत को उसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को आप इंकार नहीं कर सकते हैं और उस सिलसिले में उस चरवाहा विद्यालय को मैं मानता हूँ कि वह एक अच्छा स्टेप था, वह नहीं चला, यह अलग बात है इसलिए जब शिक्षा पर बहस करें तो आपको खुले दिमाग से बहस करना चाहिए । आपका जो अपग्रेडेड हाईस्कूल है वह बदहाल है, स्कूलों में टीचर्स के पोस्टिंग की जो हालत है, आप जानते हैं, बी0पी0एस0सी0 में लगभग चार साल होने जा रहा है, वर्ष 2013 में आपने कॉलेज के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला, 2013 से 2014 हुआ, फिर 2014 से 2019, पांच साल लग गये कॉलेज के टीचर्स के नियुक्ति में, अभी आखिरी दिनों में उर्दू बेचारी जिसको दूसरी राज्यभाषा आपने बनायी है, कंस्टीच्यूशनल पोजिशन उसको आपने दिया है बिहार में, इस कंस्टीच्यूशनल पोजिशन में उसकी बदहाली जो आपने की है कि आपके पांचवें साल में अब उसके इंटरव्यू शुरू हुए हैं । क्या कंसेसनेश है बजीर साहब, आप इस बात को दखिये कि आप किस तरह से चीजों को ले रहे हैं, उर्दू सब्जेक्ट को, मैथिली सब्जेक्ट को ,भोजपुरी सब्जेक्ट को ,बंगला सब्जेक्ट को यह इतनी बड़ी समाज की मातृजुवान है और अगर आपने उसको कंस्टीच्यूशनल पोजिशन दिया है, आपने कैबिनेट के मीटिंग में उर्दू की ताल्लुक से जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को आप इतने सालों से पूरे नहीं कर रहे हैं । यह फैक्ट है, आप कैबिनेट के डिसीजन को उठाकर देख लीजिये, मुख्यमंत्री जी जानते हैं इस बात को लेकिन बड़ी बड़ी महफिलों में डींग हांकना और उन महफिलों के चेहरों को देखकर आप कहते है कि काम हो जायेगा लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है, मैं ऐसा एम0एल0ए0 हूँ जो उर्दू स्क्रीप्ट में चिट्ठियां लिखता हूँ और इसलिए लिखता हूँ कि उर्दू सेकेंड लैग्वेज है, उर्दू सेकेंड लैंग्वेज का मतलब है कि अगर मैं बजीर को उर्दू स्क्रीप्ट में चिट्ठी लिखूं तो मैं जवाब का मुनतजीर रहूंगा कि उर्दू स्क्रीप्ट में ही वे जवाब देंगे । But you do not have translators, you have no appointment of translators, 1700 ट्रांसलेटर की जगह खाली बची हुई है जिसका आपने एनाउंसमेंट किया है This is how you run the govt., this is how you run the ministeries of education इसलिए मेरे भाई जब बात की जाती है, बात निकलेगी तो दुख तो लग जायेगी । अब नियुक्ति में आपने कुछ कुछ शुरूआत की है, लैब फैसिलिटीज के लिए हाई स्कूल में आपने कुछ पैसे भेजे हैं लेकिन पता कीजिये कि विभाग के लोग जो हाई स्कूल में लैब फैसिलिटीज के लिए पैसे गये हैं उसका किस तरह से बंदरबांट हो रहा है। आपने टीचरों को जिसका प्रथम काम पढ़ाना था उसको आपने सब चीज में लगा दिया है, बाबर्ची में भी लगाया, जनगणना में भी लगाया, इलेक्शन में भी लगाया, कंस्ट्रक्शन में भी लगाया, सिवाय पढ़ाने के आपने हर काम में उनको लगाये, बजीर

साहब, You realise the problem एक इंसान एक टीचर से आप क्या क्या काम लेना चाहते हैं इसलिए हमको यह समझना चाहिए हम शिक्षा को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपका जो बजटीय प्रोविजन है उसके बारे में मैंने बतला दिया । अब मेरी कुछ सजेशनस है, मेरी कुछ राय है आपका जो प्राईमरी, मिडिल और अपर मिडिल क्लास है वह जर्जर है, हमारे यहां एक साल से लेकर लगभग यूनिवर्सिटी के एजुकेशन तक के लिए आपका इतना बजट चाहिए, आप चाहें जितना भी पीठ थपथपायें और कहें कि हमने 35 हजार करोड़ रू0 दे दिया लेकिन ये बहुत कम है और इन पैसों में जिस तरह का करप्शन है और जिस तरह का बंदरबांट होता है या कोई योजना टाईम पर इम्पलीमेंट नहीं होता है The biggest problem is the implementation agency of this Govt. whatever they say, it has got implemented properly at the block lavel and district lavel.

सभापति(डॉ0अशोक कुमार) माननीय सदस्य, अब आपको समाप्त करना होगा ।

श्री शकील अहमद खां: एक मिनट और लेना चाहता हूँ बजीर की इजाजत से और शुक्रिया है राजेश भाई आपने मुझे वक्त दिया, बहुत जमाने के बाद मुझे बोलने का मौका मिला मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री हेड करें तमाम पोजिशन और अपोजिशन के लोगों को साथ लेकर के, एम0एल0ए0 को, मिनिस्टर को लेकर के एक ऐसी कमिटी बनायी जाय जो शिक्षा पर महीने दो महीने पर गौर करे जैसे कि 13 तारीख को आपने पर्यावरण पर कर रहे हैं । ऐसी कुछ कोशिश करें बिहार में, जैसे आप एक कमिटी बनायें, पक्ष और विपक्ष के नेता उसमें बैठे और तय करें और हर महीने दो महीने पर उसकी मोनेटरिंग हो।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) अब समाप्त कीजिये आप ।

श्री शकील अहमद खां: मेरे पास राय बहुत थी लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेथड ऑफ एजुकेशन में मदरसा एजुकेशन इम्पौरटेंट हैं मदरसा एजुकेशन में भी जो आपका कमिटमेंट है, मैं सिर्फ कमिटमेंट की बात करता हूँ जो आपने किया है जो सरकारी मदरसे हैं, वह मदरसे नहीं जो हमारे और उनके चंदे से चलते हैं, सरकारी मदरसे में जो डिस्क्रीमिनेशन है जो आपका बजटीय प्रोविजन है उनके लोग को आप पेंशन देते नहीं है, उनसे वह काम नहीं लेते जो सरकारी लोगों से काम लेते हैं तो यह सब चीजें आपको ठीक करनी चाहिए । अगर यह आप नेक नियति से ठीक करेंगे तो हमको लगता है कि आप कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ायेंगे।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) अब समाप्त कीजिये आप ।

डॉ0 शकील अहमद खां: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य,श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीनः महोदय, आज मुझे शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर बोलने का अवसर दिया गया इसके लिए मैं आसन के प्रति और अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । महोदय, निश्चित रूप से बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री कई क्षेत्रों में उन्होंने जो सराहनीय कार्य किया है और मैं यह भी नहीं कहता कि 15 साल 14 साल के शासनकाल में बिहार में कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं हुआ क्योंकि मैं अगर ऐसा कहता हूँ तो बिहार में काम करने वाले तमाम राजनीतिक, सामाजिक, पदाधिकारीगण एवं तमाम इंजीनियर और किसान सबों का जो प्रयास है उसकी मैं निन्दा करूंगा इसलिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि बिहार आगे की तरफ बढ़ा है और विभिन्न क्षेत्रों में काम हुआ है, सड़कें भी बनी है, बिजली भी सभी जगहों पर पहुंची है इसमें मुख्यमंत्री की भी कुछ भूमिका है इसलिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो बदहाली हुई है, जो गिरावट हुई है, जिस तरह शिक्षा व्यवस्था धवस्त हुआ है इसका भी मैं जिम्मेदार अगर अच्छे काम का जिम्मेदार अपने मुख्यमंत्री को देता हूँ तो बदहाल शिक्षा व्यवस्था की भी पूरी जिम्मेदारी मुख्यंमत्री को देता हूँ। अगर ताली कप्तान के लिए है तो गाली भी मुझे लगता है कि उसके कप्तान को ही मिलना चाहिए । मैंने जरूर यह शिक्षा के क्षेत्र में बतलाना चाहूंगा कि बिहार का जो शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है, आज नहीं हजारों हजार साल पहले यहां नालंदा जैसा विश्वविद्यालय हुआ करता था, यहां विक्रमशीला जैसा विश्वविद्यालय हुआ करता था और सारी दुनिया के लोग इस बिहार के धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे (क्रमशः)

टर्न-9/मधुप/05.07.2019

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : ..क्रमशः.. और पूरी दुनिया में बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता था । आज क्या स्थिति हो गई ? आज बिहार की डिग्री लेकर अगर किसी भी राज्य में जाते हैं, किसी भी बड़े शहरों में जाते हैं तो उस डिग्री पर विश्वास नहीं किया जाता है और जानता है कि यह भले ही ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आया हो लेकिन 7वॉं-8वॉं के लायक भी यह बच्चा नहीं होगा । इस बदहाल स्थिति को पैदा करने वाला कौन है ? मुझे लगता है कि इस तरह के गम्भीर विषय पर विचार करने की जरूरत है । आज लोग कहते हैं सदन में कि विधायक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़कर दिखाये, सांसद का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़कर दिखाये, आई0ए0एस0/आई0पी0एस0 का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़कर दिखाये, मैं सरकार को चुनौती देता हूँ कि शिक्षा विभाग का आज बजट है, सरकारी चपरासी का बच्चा भी अगर पूरे बिहार में कहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ता होगा तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार रहूँगा । ग्रेड-4 का कर्मचारी या चपरासी भी इस बिहार सरकार का

आपके सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है । यह बात मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ । यह प्रमाणित करता है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था किस स्तर पर चल रही है ।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कई क्षेत्रों में काम किया है, जिसकी मैंने प्रशंसा भी की । आखिर क्या कारण है कि शिक्षा विभाग के क्षेत्र में 13-14 साल के शासनकाल के बावजूद दिन-प्रतिदिन शिक्षा व्यवस्था की स्थिति गिरती जा रही है । इसपर मैं सोचता हूँ तो इसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाता है लेकिन कुछ शंकाएँ पैदा होती हैं क्योंकि आखिर क्या कारण हो सकता है ? तो मुझे एक कारण समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके संगत में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस नीति, जिस सिद्धांत पर काम करती है, वह आर0एस0एस0 की विचारधारा पर काम करता है, आर0एस0एस0 किस विचारधारा पर काम करता है ? आर0एस0एस0 मनु-स्मृति की विचाराधारा पर काम करता है । मनु-स्मृति का विधान क्या कहता है ? उसकी विचारधारा क्या कहती है ? वह वर्ण-व्यवस्था पर विश्वास करती है, वह इस व्यवस्था पर विश्वास करती है कि अछूत समाज के लोगों को और क्षुद्र समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं है । जो इस विचारधारा पर विश्वास करता हो, उसके साथ आप लगातार काम करते हैं, कहीं उसका तो यह असर देखने को नहीं मिल रहा है ! क्योंकि मैंने देश के तत्कालीन शिक्षा राज्य-मंत्री का एक बयान सुना था, श्री उपेन्द्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट रूप से एक प्रेस कांफ्रेंस करके कहा था कि देश के तमाम शिक्षण संस्थानों के सर्वोच्च पदों पर आर0एस0एस0 विचारधारा के लोगों को बैठाने का काम किया जा रहा है । वैसे विचारधारा के लोगों को बैठाने का काम किया जा रहा है जिनका उद्देश्य है कि अछूत और क्षुद्र समाज को शिक्षा के अधिकार से दूर रखा जाय, समानता के अधिकार से दूर रखा जाय, महिलाओं को समानता के अधिकार से दूर रखा जाय । उस विचारधारा के लोगों के साथ आपने रहने का काम किया है इसीलिए मुझे लगता है कि इन सबका यह सब कारण तो नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में नहीं सुधर पा रही है ! जबकि भारतीय संविधान यह कहता है कि शिक्षा के व्यापारीकरण की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, संविधान के प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य - सामाजिक-आर्थिक न्याय और सामाजिक-आर्थिक समानता और सबको समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए, ऐसा संविधान हमें कहता है ।

आज शिक्षा में जो स्थिति है, स्कूल को आप 5 केटेगरी में बॉट सकते हैं, 5 ग्रुप है स्कूल का जिसमें एक लोअर इनकम ग्रुप है, उसके लिए अलग तरह का स्कूल होता है, एक मिडिल इनकम ग्रुप है, उसके लिए अलग तरह का स्कूल होता है, एक

हायर इनकम ग्रुप है, उसके लिए एक अलग तरह की व्यवस्था होती है, एक एलिट क्लास होते हैं, उसके लिए अलग तरह की व्यवस्था है और एक व्यवस्था वह है सरकारी स्कूल, जो 5वॉं है, बी0पी0एल0 परिवार के लोग, जो गरीबी-रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोग हैं, वैसे लोग उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं और उस स्कूल में आप देखेंगे तो वहॉं इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा । सब जगह अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अलग-अलग ड्रेस कोड होता है, अलग-अलग सिलेबस होता है, अलग-अलग तरह की किताबें होती हैं । ऐसी व्यवस्था संविधान की अवधारणा के विरूद्ध है क्योंकि समान तरह का अवसर होना चाहिए, समान तरह का सिलेबस होना चाहिए, समान तरह के किताब की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि देश के किसी भी क्षेत्र में, अगर कहीं भी कोई किसी राज्य में जाता है तो उसे किसी तरह का सिलेबस या किसी तरह का अन्तर उसको नहीं सामने आना चाहिए । लेकिन इस तरह का काम किया जा रहा है ।

महोदय, यह देखता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गड़बड़ी पैदा हुई है इसका कारण क्या है, तो मुझे लगता है कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा को बेहतर बनाने का नहीं है, इसी का नतीजा इस तरह देखने को मिलता है । 'असर' एक संस्था है- Annual Status of Education Report वह लगातार पूरे देश के विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण करके यह बताती है कि किस राज्य की गुणवत्ता कैसी है । उसने रिपोर्ट दिया है लगातार, एक-दो दिन में नहीं, हर साल रिपोर्ट देता है, पिछले 5-7 साल का रिपोर्ट देखने से यह स्पष्ट होता है, 'असर' का रिपोर्ट यह बताता है कि आपके पॉंचवे-छठे क्लास के जो बच्चे हैं वे दूसरे-तीसरे क्लास के किताब को अधिकांश बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं । आपके चौथे-पॉंचवे क्लास के बच्चे गुणा-भाग नहीं कर पा रहे हैं । यह एक भयवाह स्थिति 'असर' का रिपोर्ट प्रदर्शित करता है । न केवल 'असर' का रिपोर्ट, बल्कि देश के विभिन्न संस्थाओं का रिपोर्ट जो बिहार के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का जो रिपोर्ट दे रहा है वह बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खस्ताहाल है । आप 10 और 12 में देखिये, आप अरबो रूपये शिक्षा पर खर्च करते हैं और 10 और 12 में आपके सरकारी विद्यालय के बच्चे टॉप-10 में नहीं आते हैं । इसका क्या कारण है ? अगर कहीं टॉप-10 में आते भी हैं तो पता चलता है कि वहॉं पर कुछ गड़बड़ी किया गया था। आपकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि आप कहीं टेम्पोररी शिक्षक रखते हैं, कहीं आप गेस्ट शिक्षक रखते हैं और कहीं है भी शिक्षक तो उसको आप वेतन नहीं देते हैं । वेतन मॉंगता है तो आप उसका सिर फोड़ देते हैं । ऐसी स्थिति रहती है ।

इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल स्पष्ट रूप से मानता है कि इस तरह अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए बल्कि एक

समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं और कॉमन एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल कॉमन एजुकेशन सिस्टम का समर्थन करता है ।

बिहार की स्थिति हम बताना चाहेंगे कि बिहार में प्राध्यापक जो हैं, 50 बच्चे पर एक हैं जबकि राष्ट्रीय औसत क्या है, राष्ट्रीय औसत मात्र 24 है । बिहार में लगभग पौने तीन लाख शिक्षकों की कमी है, पिछले दशकों से बात चलते आ रही है कि जस्ट वेकेंसी निकलेगा, वेकेंसी निकलेगा, तीन लाख शिक्षकों की बहाली आप नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण एक स्कूल नहीं, लगभग हजारों स्कूल ऐसे हैं, 1500 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक के भरोसे पर आप स्कूल चला रहे हैं । प्राथमिक विद्यालय को आपने मिडिल कर दिया, दो-चार सौ बच्चे बढ़ गये, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया, मिडिल स्कूल को आपने हाई स्कूल कर दिया, चार-पॉच सौ बच्चे बढ़ गये, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया, हाई स्कूल को आपने इन्टर स्कूल कर दिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया । इस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि आप इस दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं । सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि प्रत्येक पंचायत में एक उच्च विद्यालय करेंगे और अभी लगभग आधे बिहार में अभी तक यह नहीं हो पाया है जबकि 10 साल पहले यह लक्ष्य रखा गया था । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले साल जो आपने पूरे बिहार में उच्च विद्यालय की सूची जारी की, उसमें आपके बिहार के आधे जिले का एक भी स्कूल नहीं है, पूरे बिहार का मैंने उसका अध्ययन किया था, तीन-साढ़े तीन सौ स्कूल को आपने रिकोगनाइज किया था लेकिन उसमें 20 जिला का नहीं है । आखिर इसका जिम्मेदार कौन है ? आप शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमिटी बनाते हैं, वह वहॉ से अनुशंसा भेजता है कि किस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उत्क्रमित करना है । जिस शिक्षा पदाधिकारी ने आपको वहॉ से अनुशंसा पत्र नहीं भेजा, वैसे शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ....

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब कंक्लुड कीजियेगा ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : 15 मिनट टाईम है न सर ?

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : 10 मिनट ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : तो हम अपने क्षेत्र पर ही संक्षेप में अपनी कुछ बात को रखते हैं । इसी तरह प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल करने की बात थी उसमें बेजाडीह पंचायत है, छतौना पंचायत है, विक्रमपुर बांदे पंचायत है, जितवारपुर चौक पंचायत है, रहीमपुर रूदौली पंचायत है, इस क्षेत्र में हमको हाई स्कूल करना था जो नहीं किया जा सका है । 50 लाख की आबादी है, केवल दो कॉलेज में समस्तीपुर में आप पी0जी0 की पढ़ाई पढ़ाते हैं और हमारे बच्चों को, बच्चियों को दूसरे जिला में जाने पर विवश होना पड़ता

है । इसीलिए हम मॉग करते हैं कि आर0एन0आर0 कॉलेज, बी0आर0बी0 कॉलेज, महिला कॉलेज को उत्क्रमित करने का काम किया जाय ।

साथ-ही, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम यह कहते हैं कि आपके विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा का भी ख्याल नहीं रखते हैं। 2006 में, 13 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके एक स्कूल के प्रांगण में अल्पसंख्यक छात्रावास का शिलान्यास किया लेकिन आज तक उसपर काम नहीं हुआ, 10 बार विधान सभा में उठा है वह मामला । आपने पहले आर0एस0बी0 में शिलान्यास किया, 10 साल तक नहीं हुआ, फिगर बगल में दूसरे मोडल स्कूल में जाकर देखा गया, खुद अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव जाकर देखे लेकिन वहाँ तय किया गया, किसी न किसी तरह का अड़ंगा या तो हेड मास्टर या डायरेक्टर या उप सचिव या प्रधान सचिव, कहाँ पर आकर रूक जाता है और 15 साल से 25 बार विधान सभा में उठा है, इस मामला का निदान, आपके विभाग को सहमति देने का काम है जो नहीं कर पाते हैं।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : ठीक है । अब आप समाप्त करिये ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : इसलिये मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो आवश्यक कदम हैं, उनको उठाना चाहिए । इन्हीं चन्द बातों के साथ मैं अपने नेता के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : धन्यवाद ।

माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार । 10 मिनट आपको बोलने का समय है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, आज शिक्षा विभाग का बजट पेश हुआ है, शिक्षा विभाग के मॉग के पक्ष में मुझे आज बोलना है । महोदय, 347 अरब 98 करोड़ 69 लाख 44 हजार रू0 का बजट पेश हुआ है । महोदय, एक समय था बिहार में 2005-06 में, शिक्षा का बजट 4261 करोड़ था और फिर वही बजट बढ़ते हुए 2018-19 में 34 हजार करोड़ रू0 हो गया ।

...क्रमश:....

टर्न-10/शंभु/05.07.19

श्री जितेन्द्र कुमार : क्रमश:..यानी की पूरे बिहार के बजट का 20 परसेंट बजट, जो रूपया खर्च हो रहा है वह शिक्षा पर हो रहा है । यानी कि सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर है । हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण धन है, एक महत्वपूर्ण शस्त्र है, एक अनमोल धन है। जब कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वह आत्मनिर्भर हो जाता है, स्वाबलंबी हो जाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वह किसी का बोझ नहीं बनता । मैं कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उससे उसकी शिक्षा को कोई छीन भी नहीं सकता है, चोर चोरी भी नहीं कर सकता है, डकैत डकैती भी नहीं कर सकता है,

किडनैपर किडनैपिंग भी नहीं कर सकता है शिक्षा का। जो शिक्षा है वह एक सच्चे मित्र की तरह जीवन पर्यन्त मनुष्य के साथ रहता है मुश्किलों में, हर झंझावात में, हर परिस्थिति में एक सच्चे मित्र की तरह रहता है और इस मर्म को हमारे माननीय नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समझा है । मुझे 2005 में विधायक बनने का मौका मिला और 2005-06 में गांव में स्कूलों की स्थिति क्या थी- भवन नहीं थे, शिक्षक नहीं थे, लेकिन आज दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि हर गांव में आज प्राथमिक विद्यालय के एक अच्छे भवन हैं और अच्छे स्कूल हैं जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं । मैं यह नहीं कहता कि सबकुछ हो गया स्थिति क्या थी और यह हमारी पराकाष्ठा भी नहीं है । हमारे नेता भी कहते हैं कि यह हमारी पराकाष्ठा नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है । यह निरंतर चलनेवाली चीज है, लेकिन यह तुलनात्मक अध्यन करने की बात है कि लगातार हम आगे की ओर जा रहे हैं । एक समय था कि हमलोगों के बच्चे यहां से पलायन कर रहे थे क्योंकि बिहार पढ़ने की जगह नहीं थी, यहां स्कूल में पढ़ाया नहीं जा सकता था, खुशनुमा माहौल नहीं था, भय का वातावरण था, किडनैपिंग का माहौल था, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी । आज विधि व्यवस्था अच्छी है, आज खुशनुमा माहौल है, आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सभापति महोदय, उसी का नतीजा है कि हम भी कोई बूढ़ा नहीं हैं, हम भी पटना में पढ़ते थे और गांव में पढ़ते थे, बिहारशरीफ में पढ़ते थे जिस क्षेत्र से आते थे । जब मैं पटना में हाईस्कूल में पढ़ता था तब लड़कियां कोई साइकिल से आती थी तो लोग घूरकर देखते थे ऐसी मानसिकता थी, लेकिन आज गांव की पगडंडियों पर लड़कियां साइकिल चला रही हैं । क्या यह विकास नहीं है ? यह एक सामाजिक क्रांति है । एक पिन ड्रॉप साइलेंस रिवोल्यूशन है कि गांव की पगडंडियों पर लड़कियां साइकिल चला रही हैं निर्भीक होकर, निर्भीक होकर जा रही है ट्यूशन पढ़ने, स्कूल जा रही है यही तो क्रांति है और यही माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है । आज एक खुशनुमा माहौल हुआ है आज लड़कियां अपने विवेक से पढ़ रही है लिख रही है, यह स्थिति है । वर्ष 2018 के मैट्रिक परीक्षा में छात्र एवं छात्राओं की संख्या बराबर-बराबर थी, यानी 50/50 परसेंट । एक जमाना था गैपिंग था, हमारे पूर्व के सदस्य बता रहे थे कि जब हम पढ़ते थे तो क्लास रूम में लड़कों की संख्या 127 और लड़कियों की संख्या केवल 27 थी। इस गैपिंग को पूरा किया गया है महोदय अब महिलाओं की भागीदारी, लड़कियों की भागीदारी भी परीक्षा में बिलकुल आधा-आधा हो गया है मतलब जनसंख्या की आधी आबादी है उनको भी आज कदम से कदम मिलाने का पूरा अधिकार सरकार ने दिया है और यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच है । यह माननीय मुख्यमंत्री जी के सृजन की सोच है, एक रचनात्मक विचार है जिसके चलते

आज स्कूल-कॉलेज बेहतर हो रहे हैं । महोदय, हायर एजुकेशन तो कोई चीज ही नहीं थी बिहार में, लोग बाहर चले जाते थे इंटर करने के बाद कर्नाटक चले गये, महाराष्ट्रा चले गये, केरल चले गये। आज अच्छे-अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, पॉलीटेक्नीक कॉलेज खुले हैं, आइ0टी0आइ0 महिला कॉलेज खुल रहे हैं, आइ0टी0आइ0 कॉलेज खुले हैं, आर्यभट्ठ ज्ञान विश्वविद्यालय खुले, चाणक्य लॉ युनिवर्सिटी खुले । युनिवर्सिटी खुले यानी की सारी व्यवस्थाएं आ रही हैं, सारी संस्थाएं आ रही हैं । एक समय था जब हमलोग नालन्दा का नाम लेते थे, नालन्दा से मैं आता हूॅं और वहां पर एक धरोहर के रूप में हमलोग देखने जाते थे नालन्दा विश्वविद्यालय, लोग धरोहर के रूप में देखने जाते थे । यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि युनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा नये सिरे से वहां पर स्थापित हुआ और यह केवल बिहार का या देश का नहीं पूरी दुनिया का युनिवर्सिटी हो गया । यह हमलोगों के लिए गौरव की बात है कि इतने अच्छे कार्य हुए हैं कि देश-विदेश के लोग आ रहे हैं । बिहार का जो प्राचीन काल में गौरव था, जो ज्ञान की भूमि थी उस गौरव और सम्मान को पाने के लिए हमारे नेता लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं । इसलिए हम अपने नेता पर फख्र करते हैं, गौरव करते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच केवल खाका तैयार करना ही नहीं होता है, केवल शिलान्यास करना नहीं होता है वे उस कार्य को अमलीजामा पहनाने का काम करते हैं । इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभारी हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कई लोग कहते हैं विपक्ष के कि बिहार में काम नहीं हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, स्कूल नहीं खुले, कॉलेज नहीं खुले, लेकिन अगर वही अपने घर में बैठते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि बिलकुल नीतीश कुमार जी की रहनुमाई में काम हुआ है, तरक्की हुआ है इसे मानते हैं । भले राजनीतिक कारणों के कारण कह दें कि विकास नहीं हुआ तरक्की नहीं हुआ है । आज बात किया जाय जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो प्लस टू के बाद पढ़ाई नहीं कर सकते थे उन्हें भी अधिकार है हायर एजुकेशन लेने का, इंजीनियर बनने का, डाक्टर बनने का उनके लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गयी है । वह भी काम कर रहे हैं । वह भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं । सभी लोग सुन रहे हैं । हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे प्रधान सचिव बैठे हुए हैं वे लोग लिख रहे हैं । आज जितनी बातें बोलते हैं उसपर अमल कर रहे हैं । आपके क्षेत्र में भी आप 2005 के पहले देखे होंगे कि स्थिति क्या थी और आज आप भी जाते होंगे तो जरूर महसूस करते होंगे । इसलिए कहते हैं जब घर मैं बैठते हैं आपलोग तो माननीय नीतीश कुमार जी की चर्चा करते हैं कि निश्चित तौर से विकास हुआ है, भले आज आप बोल लीजिए, लेकिन जब लौबी में जाइयेगा तो कहियेगा कि सच में जितेन्द्र जी नीतीश जी की रहनुमाई में काम हुआ है और गौरव

होगा, अच्छा भी लगता है । स्टूडेंट क्रेडिट की बात ले लीजिए महोदय, इसमें छात्रों को 4 परसेंट पर ऋण मिल रहा है, लड़कियों के लिए 1 परसेंट पर, दिव्यांग के लिए 1 परसेंट पर यही तो विकास है । हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं । मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना- महोदय, लड़कियों की शिक्षा बढ़ाने के लिए जो इन्टर पास करती हैं कोई वर्ग भेद नहीं किसी कोटि की हो 10 हजार, स्नातक पढ़ लेते हैं तो उनको भी 25 हजार हमलोग लगातार प्रयास कर रहे हैं । महोदय, अब पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे संस्कार आने चाहिए इसकी चर्चा होते रहती है । नैतिकता मोरल की बात होती है क्योंकि पढ़ाई करनेवाले लोग, शिक्षित लोग भी भाई चारा भूल गये, मोहब्बत भूल गये, भाई-भाई का क्या संबंध होना चाहिए, बाप बेटे में क्या संबंध होना चाहिए, दोस्त-दोस्त में क्या संबंध में होना चाहिए । इसमें कहीं न कहीं गिरावट आई है । महोदय, नैतिकता का पतन हुआ है । माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए कटिबद्ध हैं । उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया है और उन्होंने गांधी जी की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करने के लिए कई कार्यक्रम चलाये हैं । स्कूलों के सिलेबस में एक था मोहन और बापू की पाती का भी बात किया गया है जो सिलेबस में है । इसलिए उनके विचारधारा को अपनाने से ही हम सभी का विकास हो सकता है, नैतिकता आ सकती है और एक भाईचारे का माहौल हो सकता है, संस्कार बन सकता है । हम चाहेंगे कि कई तरह के कुछ सुझाव भी हैं । मैंने पहले ही कहा कि यह पराकाष्ठा नहीं है आगे निरंतर बढ़ना है, कमियां है, खामियां है उसको भी देखना है और उसको देखते हुए आगे की ओर बढ़ना है । महोदय, हमारा सुझाव है कि जिन जगहों पर आपने हाईस्कूल खोला है, आपने मॉडल विद्यालय खोला है लेकिन वहां पर शिक्षक नहीं हैं, वहां पर उपस्कर नहीं है । यहां पर प्रधान सचिव बैठे हैं और मंत्री जी भी बैठे हैं । मैं कहना चाहूंगा सच बात है, मैं कहना चाहूंगा यह कोई राजनीति करने की बात नहीं है । विधायक जी इसमें राजनीति करने की बात नहीं है, बच्चों की बात है इसपर विवाद मत कीजिए । हमने कहा कि अभी विद्यालय खुले हैं, हाईस्कूल खुले हैं वहां शिक्षा तभी होगा जब वहां पर टीचर होंगे, टीचर होंगे उपस्कर होंगे, प्रयोगशाला होंगे । क्रमशः...

टर्न-11/ज्योति/05-07-2019

क्रमशः

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, हम कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री महोदय से कि हरेक हाई स्कूल में विषय वार शिक्षक दें ।

(व्यवधान)

आपकी बात हम कह रहे हैं कि हमलोग वैसी सरकार में है जो अपनी कमियों को देखकर दूर करने का प्रयास करते हैं । इसलिए समय जाया नहीं करिये । महोदय, शिक्षक विषय वार होना चाहिए । हाई स्कूल में शिक्षक हैं तो कहीं उर्दू की आवश्यकता नहीं है तो वहॉं पर उर्दू के शिक्षक आ जाते हैं इसलिए विषय वार शिक्षक संतुलित तरीके से हों इसलिए मैंने कई बार माननीय मंत्री जी को अवगत कराया कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षकों की कमी है । कहीं सायंस के टीचर नहीं हैं, कहीं संस्कृत के टीचर नहीं है हम चाहते हैं कि फेयर एग्जाम हो लेकिन फेयर पढ़ाई भी हरेक घंटी की पढ़ाई हो । हम कहना चाहते हैं कि हर स्कूल में पूरी घंटी की पढ़ाई हो, इसको ढंग से देखने की आवश्यकता है । इसमें कोई राजनीति नहीं विधायक जी, यह सब की बात है, बच्चों की बात है सबको आगे ले चलने की बात है । हम मंत्री महोदय से भी कहना चाहेंगे और मेरा सुझाव है कि हर प्रखंड में एक शिक्षा पदाधिकारी निश्चित रुप से पदस्थापित हों । एक शिक्षा पदाधिकारी चार जगह के प्रभार में, पॉच जगह के प्रभार में, समीक्षा नहीं हो पाती है, हमारे अस्थावां, हमारे बिन्द में, हमारे कतीसराय में, हमारे सरमेरा में एक ही शिक्षा पदाधिकारी चार जगह के प्रभार में हैं, उसके अलावा क्या ? जिला के प्रभार में । इन चीजों को महोदय, देखने की आवश्यकता है ताकि बेहतर ढंग से समीक्षा हो सके । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सात निश्चय की बात की है । उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हायर एजूकेशन नहीं ले पाते हैं उन्हें भी हुनरमंद बनाया जाय, उन्हें भी अपने पैरो पर खड़ा होने की व्यवस्था की जाय, और इसलिए युवाओं पर बल दिया गया है, उन्हें कम्पयूटर की शिक्षा प्राप्त हो । उन्हें हुनरमंद बनाया जाय, उनकी तकनीकी शिक्षा हो ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आत्म निर्भर हो सके इसलिए उसपर जोर दिया गया है । हम चाहेंगे कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में हमने कई बार कहा भी है कि बिंद उच्च विद्यालय है, प्रखंड मुख्यालय में बिंद उच्च विद्यालय बहुत ही पुराना स्कूल है और उसका भवन जर्जर हो गया है । कई बार हमने कहा है, समीक्षात्मक बैठक में भी कहा है और वह भवन नहीं बन पाया है । 2000 बच्चे पढ़ते हैं तो मैं चाहूंगा कि लुक भी अच्छा हो जाय बेहतर हो जाय एक इन्वायरमेंट बने, इन चीजों को देखने की आवश्यकता है । कुछ विधायक जी ने कहा कि कुछ जगह पर जो हमारे प्रभारी प्राचार्य हैं वे उपस्कर की प्रयोगशाला में खरीद करते हैं, उसकी गुणवता पर ध्यान नहीं देते हैं। उसमें विधायक की भूमिका नहीं है । प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष भले विधायक हैं लेकिन विधायक की भूमिका नहीं है तो हम चाहेंगे कि इसपर जोर दिया जाय और विधायक की उसमें भूमिका हो कि प्रभारी प्राचार्य ने किस सामान की

खरीद की, उसकी गुणवता क्या हो और अंतिम रुप से विधायक की सहमति जरुर ली जाय ताकि बेहतर सामान खरीद हो क्योंकि विधायक उस क्षेत्र से हैं, विधायक की एक जिम्मेदारी है और विधायक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि उस स्कूल में अच्छे उपस्कर के सामान हो, अच्छे प्रयोगशाला के सामान हो, अच्छे पूस्तकालय के सामान हो और अच्छी तरह से विद्यालय चले एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है इसलिए इसपर मंत्री महोदय से जरुर कहेंगे प्रधान सचिव भी बैठे हैं, इसकी प्रबंधकारिणी समिति के बिना कोई भी क्रय विक्रय या अन्य कार्य नहीं हो । विधायक ही अध्यक्ष होते हैं उनकी भूमिका होनी चाहिए । हम यह महोदय, कहेंगे कि मुझे गौरव होता है ..

सभापति(श्री अशोक कुमार): अब आप समाप्त करें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अंत में महोदय, मुझे गौरव होता है कि मुझे विधायक बनने का मौका मिला 2005 से अबतक का मुझे खुशी होती है कि आदरणीय नीतीश कुमासर जी की रहनुमाई में, मैं विधायक बना और उनकी छत्रछाया में काम करने का मौका मिला है और लगातार मैंने देखा है कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी । आज क्या स्थति है, निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच है । उनके सकारातमक सोच के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे । आपने मुझे मौका दिया इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों का विराम करते हैं । जयहिंद, जय बिहार ।

सभापति(श्री अशोक कुमार): माननीय सदस्या श्रीमती अरुणा देवी ।

श्रीमती अरुणा देवी: सभापति महोदय, 2019-20 शिक्षा विभाग का जो बजट पेश किया गया है और कटौती प्रस्ताव के विरोध में सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, राज्य सरकार शिक्षा की गुणवता, सुधार तथा शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को सभी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कृतसंकिल्पत है । महोदय, इसी कारण राज्य की एन.डी.ए. सरकार द्वारा शिक्षा पर सबसे अधिक राशि का प्रावधान किया गया है । एन.डी.ए. सरकार बनने के बाद अबतक 2 लाख 27 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। सभापति महोदय, जहाँ वर्ष 2005-06 में बिहार के लिए शिक्षा का बजट 4 हजार 2 सौ 61 करोड़ रुपये का वहीं 2019-20 में बजट 34 हजार 7 सौ 98 करोड़ रुपये का है । सभापति महोदय, साईकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृति योजना आदि के लागू होने से राज्य में बालिका शिक्षा में उन्नति प्रगति हुई है । वर्ष 2018 की मैट्रिक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में बालिकाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत तक पहुंच गयी है । सभापति महोदय, राज्य सरकार स्कूल में पढ़ने वाली स्र्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दे रही है जिसके लिए मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किया गया

जिसके तहत सेनेटरी नैपकिन के लिए राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 2018-19 में 3 सौ रुपये कर दिया गया है । मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत नवीं से, बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को पोशाक खरीदने हेतु दी जाने वाली राशि को 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा कन्या उत्थान योजनान्तर्गत वर्ष 2018-190 से इन्टरमीडियेट वार्षिक परीक्षा 2018 में सभी कोटि के उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को प्रति छात्रा 10 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है । महोदय, राज्य की एन.डी.ए. सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक पास बालिकाओं को प्रति छात्रा 25 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में तीन नये विश्वविद्यालय यथा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, तथा पूर्णिया विश्वविद्यालय सहित छः निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है । सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा जमुई में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है । सरकार द्वारा शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाने के फलस्वरुप महिला शिक्षकों की संख्या 39 प्रतिशत बढ़ गयी है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा 2018-19 में वर्ग 1 से आठ तक छात्र छात्राओं के पाठ्य पुस्तक किताब खरीदने के लिए उनके खाते में राशि उपलब्ध करायी जा रही है । 1.29 करोड़ छात्र छात्राओं को राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है । महोदय, वर्ष 2018-19 में वृद्धा पेंशन तथा विधवा पेंशन तथा नि:शक्त पेंशन योजना अनतिर्गत लगभग 62.46 लाख पेंशन धारियों कों डी. बी.टी. माध्यम से दिया गया है । पेंशन भुगतान किया जा रहा है । महोदय, राज्य सरकार मुख्यमंत्री बाल विवाह प्रोत्साहन योजना से राज्य की जनता को काफी लाभ हो रहा है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा प्रधान मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्मर पर सुधार लाने तथा गर्भावस्था के समय वजन की कमी हो उसके लिए भी सरकार ने सराहनीय काम किया है ।

क्रमशः..

टर्न-12/05.07.2019/बिपिन

श्रीमती अरूणा देवी : क्रमशः... सुधार करने के प्रथम जीवित संतान तक सशक्त नगद लाभ की राशि पांच हजार रूपए के भुगतान तीन किस्तों में डी.बी.टी. की माध्यम से किया जा रहा है। महोदय, राज्य सरकार के द्वारा लक्षित समूह के 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के

समाज में पालन-पोषण एवं उनके गैर-सांस्थयिक देख-रेख को प्रोत्साहित करने के लिए परिवर्तित योजना की शुरूआत की गई है जिसमें अनुदान भत्ता के रूप में एक हजार रूपए प्रतिमाह दिया जाता है । वर्ष 2018-19 में इस योजना अंतर्गत प्रावधान किया गया राशि शत-प्रतिशत खर्च किया गया है । महोदय, आई.टी.आई. प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के तहत अब तक कुल 4490 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 3660 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ।

महोदय, राज्य सरकार द्वारा दरभंगा एवं भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की शाखा बक्सर के आई.टी.आई., मुजफ्फरपुर के ए.आई.टी. में की गई है । बिहटा में आई.टी. पार्क स्थापित किया जा रहा है । महोदय, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय के अंतर्गत राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में नि:शुल्क वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 319 संस्थानों में वाई-फाई स्थापित किया जा चुका है । महोदय, आज जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि शिक्षा में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, जो हाई स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है उसमें टीचर नहीं है । ठीक है, आपकी बात है कि टीचर की कमी है लेकिन पढ़ाई में हमलोग बिहार में आगे बढ़ रहे हैं । जैसा कि आप बोलते हैं, सुनिए, वर्ष 2000 में चरवाहा विद्यालय था और कहा गया था कि गाय, बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए । उस समय विद्यालय में बकरी बंधाता था । आज तो विद्यालय में टीचर की कमी है लेकिन पढ़ाई तो हो रही है । आने वाले समय में, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और चिंतित हैं कि आने वाले समय में बेहतरीन-से-बेहतरीन विद्यालय के शिक्षक पूरा करें और हर विषय के शिक्षक उपलब्ध कराएं । तो हम समझते हैं कि कहा गया है कि -

सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से,
खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से ।

महोदय, आज मुख्यमंत्री में सच्चाई है, ईमानदारी है तभी तो बिहार की जनता ने जनादेश दिया और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की उन्नति होगी और बिहार एक दिन आगे बढ़ेगा, बिहार का नाम रौशन होगा । हम समझते हैं कि आने वाले समय में नीतीश जी का फिर जय-जयकार होगा और नीतीश जी को हमलोग धन्यवाद देते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हैं कि बिहार में जो गढ़े में रोड था और गढ़े में चलता था आदमी । हम नवादा, हिसुआ से आते थे । चार-पांच घंटा लगता था लेकिन आज जो है ढाई-तीन घंटा में हम पटना पहुॅंचते हैं । देख लीजिए आंख खोलकर कि आपके समय में कितना विकास हुआ और हमारी सरकार जो है इनके समय में कितना विकास हुआ है । जो सच्चाई है उसको सच कहिए । (व्यवधान)

एकदम झूठ सफाई नहीं दीजिए । समझे न ! नहीं तो जनता आने वाले समय में माफ नहीं करेगी । हमारा जो केंद्र की सरकार है, बिहार की सरकार है, हर व्यक्ति के लिए चिंतित है, हर वर्ग के लिए चिंतित हैं और कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास । तभी बिहार आगे बढ़ेगा और बिहारी आगे आने वाले समय में, हम समझते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचेगा और फिर 2020 में जो आने वाला चुनाव है, पूरे बहुमत के साथ नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसके साथ मैं शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और सभी को मैं धन्यवाद देती हूं । साथ ही क्षेत्र के लोगों को भी जिन्होंने हमको जीता कर भेजे हैं उन सभी माननीय जनता को भी धन्यवाद देती हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द, जय भारत, जय बिहार ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य,श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, एक तो माननीय मंत्री जी को जो अपना वक्तव्य पढ़ना है उसको भी सर्कुलेट किया गया है सभी माननीय सदस्य को और दूसरा शिक्षा विभाग का प्रतिवेदन भी सर्कुलेटेड है ।

अब महोदय, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा । उर्दू बोलते हैं, शेरो- शायरी करते हैं । अच्छे मित्र हैं । थोड़ा बख्शना भी जरूरी है मगर फिर भी महोदय, हमारा जो दायित्व है, सरकार को आइना दिखाने का, वह दिखाना जरूरी है । अब आइना हमारे दिखाने से पहले सत्ता पक्ष के जो कुछ माननीय सदस्थ थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उन्होंने भी आइना दिखाया है कि सच्चाई क्या है । अब महोदय, शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें 347 अरब 98 करोड़ 69 लाख 44 हजार रूपए के प्रावधान का प्रस्ताव ये लाए हैं सदन के पास । इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 144 अरब 89 करोड़ 66 लाख 44 हजार रूपए हैं और जो वार्षिक स्कीम है उसके लिए 203 अरब 09 करोड़ तीन लाख रूपए का प्रस्ताव है, वगैरह वगैरह ।

महोदय, अब मैं, बहुत ज्यादा झूठ तो आप नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं, मगर इन्होंने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है हमलोगों के समक्ष, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती राज्य सरकार मनाने जा रही है और महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्त किए गए विचार से इन्होंने अपने प्रतिवेदन में अपनी बातों की शुरूआत की है, अब उसको दुहराना ठीक नहीं है, मगर अब पूरे प्रतिवेदन में और आपके इस वक्तव्य में महात्मा गांधी जी ने जो नींव डाली थी जिन विद्यालयों की, उसका कोई उल्लेख नहीं है । बेसिक स्कूल में किसी में 12 एकड़, किसी में 20 एकड़ जो जमीनें हुआ करती थी महोदय, उसके बारे में, महात्मा गांधी जी को सिर्फ जश्न मनाने से उनकी 150 वीं जयंती हो जाएगी । नाच-गाना समारोह करने से हो जाएगी । मगर जो बेसिक स्कूल है, बहुत सारे हाई स्कूल में भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन नहीं है जो बेसिक स्कूल

में है मगर आपका विभाग या आप बेसिक स्कूल पर चुप हैं । झूठ-मूठ का गांधी जी, गांधी जी, अरे ! अब गांधी जी को राष्ट्रपिता आप मानते हैं, देश मानता हैं, मगर आप जिनके साथ बैठे हैं वह तो अब महात्मा गांधी जी को भी राष्ट्रपिता मानने के लिए तैयार नहीं हैं । अब उनका अगर चलेगा तो नाथूराम गोडसे राष्ट्रपिता हो जाएंगे । एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता से नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहवा कर दिखा दीजिए, मैं उनका मुरीद हो जाऊंगा ... क्रमशः

टर्न : 13/कृष्ण/05.07.2019

श्री अब्दुलबारी सिद्दीकी : (क्रमशः) मगर ये नाथु राम गोडसे मुर्दाबाद नहीं कह सकते हैं । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय हरि नारायण बाबू भी शिक्षा मंत्री रहे हैं और आप भी देहात में पढ़े होंगे, देहात के स्कूल को देखा होगा, मैं तो पटना में पटना हाई स्कूल में पढ़ा था, माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के बारे में तो बहुत कम जिक्र है इसमें, जो पटना कॉलेज है, साईंस कॉलेज है, बी0एन0 कॉलेज है, नेशनल मूवमेंट की देन थी बी0 एन0 कॉलेज, उसी तरह दरभंगा का सी0 एम0 कॉलेज, मुजफ्फरपुर का एल0 एस0 कॉलेज, भागलपुर का टी0 एन0 बी0 कॉलेज । अब आप अपने सीने पर हाथ रखकर सिर्फ इतना बता दीजिये सच सच, हमलोग पास कर देंगे । बता दीजिये कि पहले का जो प्रीमीयर इन्स्ट्यूशन था साईंस कॉलेज में कितने टीचर हैं, पटना कॉलेज में कितने टीचर हैं, यह आप बताईयेगा, नहीं बताईयेगा । पटना हाई स्कूल का हमारे सेक्शन का पूरा लड़का फर्स्ट डिवीजन में उस जमाने में पास करता था । उसका ओल्ड ब्यायज एसोसियेशन भी हमलोग बनाये हुये हैं, जिसको चलाते हैं । मगर पटना हाई स्कूल की दुर्दशा, पटना कॉलेजिएट स्कूल की दुर्दशा, राम मोहन राय सेमिनरी की दुर्दशा इतने जो प्रीमीयर इन्स्ट्यूशन थे और मैं आपको कह सकता हूं कि जिसके आकर्षण में आज का युग बह रहा है, सेंट माईकल, डी0पी0एस0 वगैरह वगैरह तो सेंट माईकल के लड़के और सेंट जेवीयर के लड़के भी नाम कटाकर ललायित रहते थे कि पटना हाई स्कूल और पटना कॉलेजिएट में कैसे हमारा एडमीशन हो जाय । अब आप बताईये कि आपकी क्या स्थिति है ?

महोदय, जिस विभाग में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, उस विभाग की राशि उतनी ही ज्यादा है । अब इस वजह से यह नहीं कि तुलना, अब आपका 15 साल हो गया, आपके यहां भी बहुत सारे लोाग जेल गये, आपकी पार्टी के लोग भी जेल गये , अब आप अपने जवाब में यह तो बताईयेगा नहीं कि जो प्राईमरी एजुकेशन है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत तो शेयरिंग राशि थी, पहले यू0पी0ए0 सरकार के समय में क्या थी

और अभी एन0डी0ए0 सरकार के समय में क्या है, 50-50 हो गया न कि 75-25 है अभी ? नहीं, 50-50 हो गया । अब उससे विद्यालय का भवन चमका, भवना बना, भवनों का निर्माण हुआ और मध्याह्न द्वारा गरीबों के बच्चों का स्कूल जाने का, पेट भरने का एक आकर्षण बना, मगर प्राईमरी एजुकेशन से सेकेंडरी एजुकेशन में जो पास करके जाते हैं उनका ड्रॉप आउट कितना है सेकेंडरी में और सेकेंडरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन में जो जाते हैं उनका ड्रॉप आउट कितना है इसी का आंकड़ा सिर्फ आप बता दीजिये ।

महोदय, अब तो चूंकि सरकार है, दिल्ली की सरकार, अपार बहुमत की सरकार और यहां की भी सरकार । हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक तरह से प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाय। मैं तो कहूंगा कि आप एक प्रस्ताव लाईये सदन में कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे केन्द्र सरकार । बिहार में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है और जगह-जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है । सिर्फ गुजरात एण्ड कंपनी मत बनाईये । जब आपका उसमें शेयर है तो झपट लीजिये न, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ।

महोदय, अब जो हमारे समय में जो स्कूल थे, उसमें स्पोटर्स के क्लास भी हुआ करते थे, उसमें एम0टी0 का क्लास भी हुआ करता था, मैनुअल ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं काष्ठ कला से लेकर सब कुछ, वह सब बंद हो गये, पुरानी व्यवस्था खत्म हो गयी । मैं कह सकता हूं कि पटना हाई स्कूल का साईंस का लेबोरेटरी, महोदय, बहुत सारे अच्छे और नामी-गिरामी कॉलेजों में लेबोरेटरी होगा, अब अगर आपको मौका मिला, पटना हाई स्कूल जाने का तो वहां का लेबोरेटरी और वहां के टीचर की स्थिति, वहां के नियमित शिक्षक और कांट्रैक्ट वाले जो हैं, वह आप देख लीजियेगा ।

महोदय, अब हमारे बिहार के लड़के अच्छे कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है । मगर आपकी शिक्षा बदौलत नहीं । आप कभी चले जाईये भिखना पहाड़ी, आप चले जाईये मुसल्लहपुर, आप चले जाईये कंकड़बाग, आप चले जाईये बोरिंग रोड तो गाड़ी चलना मुश्किल हो जायेगा । जितने कोचिंग इन्स्टीच्यूट वहां खुले हुये हैं और उन कोचिंग इन्स्टीच्यूट्स की जो मनमानी है, उस पर आपका किसी तरह नियंत्रण नहीं है । हमारे यहां का एक लड़का मिला, देखा कि वह बड़ी गाड़ी से आया, बड़ा साधारण आदमी था, हमने कहा कि गाड़ी लिये? क्या कर रहे हो आज कल तो कहां कि सर, एक कोचिंग इन्स्टीच्यूट चला रहे हैं, इसमें इतना शिफ्ट हम चलाते हैं । भई, कोचिंग इन्स्टीच्यूट का कोई रूल रेगुलेशन कौन तय करेगा ? ठीक है, आप के स्कूल, आपके

कॉलेज में अगर ऐसी पढ़ाई रहती तो लड़के कोचिंग इन्स्टीच्यूट क्यों जाते? कोचिंग इन्स्टीच्यूट में लोग जा रहे हैं । अब महोदय, हम इनको कितना आईना दिखायें ।

महोदय, अब जो है मदरसा का आपने कुछ जिक्र किया है कि यह करेंगे, यह योजना है, फलां योजना है । एक तो अब पता नहीं, जमीन अभी भी मिला कि नहीं मिला, मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी को, कितने साल हो गये, 30 साल हो गये न । कुछ हमारा साल और कुछ आपका साल, ठीक है । मगर जिसमें आपकी प्रायोरिटी होती है, शहर में जिसका चेहरा चमकाना होता है और लोग कहते हैं कि वाहवाही होगी इसको करने से, वह आप की प्रायोरिटी है। मगर आपने मदरसा के जो फर्स्ट डिवीजन पास करनेवाले बच्चे के लिये जो आपने घोषणा की तो आपने संस्कृत पढ़नेवाले को क्यों महरूम कर दिया ? मदरसा वाले को जब आप दीजियेगा तो संस्कृत पढ़ना कोई गुनाह है क्या ? संस्कृत जो पढ़ रहा है और उसमें जो प्रथम श्रेणी में पास कर रहे हैं तो उनको भी आप मदरसा की तरह, अन्य की तरह आप दीजिये ।

महोदय, इनके यहां जो शिक्षा विभाग है और स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग को तो छोड़ दीजिये, अगर काम कराना हो तो बाबु को वहां पकड़िये । बाबु तो समझ ही रहे हैं न मंत्री जी ? बाबु को जब पकड़ियेगा तो काम अगर उसको काम करना है, गुरू दक्षिणा देने के बाद तब वह पांच तरह का सरकुलर रखता है, करना है तो ये, नहीं करना है तो ये, अगर इसको फंसा कर रखना है तो ये, वगैरह वगैरह । जब शिक्षा विभाग को इतनी बड़ी राशि प्रदान की जा रही है तो अब शिक्षा का स्तर ऐसा बना दीजिये कि फिर से हम गर्व से कह सके कि पटना हाई स्कूल में हम पढ़ते थे । बी0 एन0 कॉलेज में पढ़ते थे, पटना कॉलेज में पढ़ते थे, साईंस कॉलेज में पढ़ते थे, मगर आज जो लड़का पढ़ने के लिये बाहर जा रहा है, वह अच्छा कर रहा है और अच्छा करके आपके बिहार का नाम रौशन कर रहा है कि बिहार का यह लड़का आई0ए0एस0 में चला गया है, बिहार का लड़का आई0आई0टी0 में चला गया मगर यह बताना न चाहिए कि कौन इन्स्टीच्यूट से ? यहां से ? तो जितना पैसा आप का जा रहा है कोटा में, दिल्ली में, कोचिंग इन्स्टीच्यूट में उसको अगर आप कुछ ऐसा रेगुलर सिस्टम बनाईये, जिससे आपको आमदनी भी हो और शिक्षा का स्तर भी सुधरे ।

क्रमशः...

टर्न-14/अंजनी/05.07.19

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : हम माननीय मंत्री जी को इतना ही कहकर माफ करते हैं कि हमारी बात को छोड़िए, सत्ता पक्ष ने जो आईना दिखाया है, हम तो विपक्ष में हैं, मगर विपक्ष का भी काम है आईना ही दिखाना और सरकार वही संवेदनशील होती है जो आईना

दिखाता है, उसको शिरोधार्य करती है और उस पर कार्रवाई करके उसका निदान निकालती है । मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप बेसिक स्कूल पर गांधी जी का 150 वां साल और जो हमारी प्रीमियर इन्स्टीच्यूट हैं, ठीक है, उनको आप फेजवाइज कीजिए । फेजवाइज जो अच्छे इन्स्टीच्यूट हैं उनको तो कम-से-कम सारी सुविधा सम्पन्न करा दीजिए ताकि वहां लोग जायें और आयें । चूंकि इस विभाग में लूट है, खसोट है, भ्रष्टाचार है, बहुत लेन-देन है, बहुत तरह का फर्जी कारोबार है और फर्जी कारोबार का उदाहरण जेल में गये हुए कई लोग हैं, इसलिए जितना आप खर्चा करते हैं । अंत में माननीय मंत्री जी से यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हर साल आप अपना बड़ा बजट लेते हैं, क्या शत्-प्रतिशत खर्च कर पाते हैं ? कितना पैसा लैप्स करते हैं, क्यों वह पैसा लैप्स होता है, सदन की अनुमति लेकर आप जाते हैं तो सदन को आप यह क्यों नहीं बताते हैं कि माई-बाप, हमने इतना की अनुमति ली थी आपसे, मगर हमारे निकम्मेपन के कारण इतना ही पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा लैप्स कर गया, आगे से हम लैप्स नहीं करेंगे, इसलिए शिक्षा की स्थिति सुधरे, हम भी चाहते है, और आप भी चाहते हैं, सत्ता पक्ष भी चाहता है, विपक्ष चाहता है तो सब लोग मिलकर आज जरूर घोषणा कीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का एक प्रस्ताव आपही के जवाब में आप कहियेगा हाथ उठाने, हमलोग हाथ उठा देंगे तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए और जो हमारे प्रीमियर इन्स्टीच्यूट थे, उसकी इज्जत वापस लाइए तब तो ठीक है, नहीं तो अभी तो हम सिम्बोलिक दस रूपया ही कम करने का मांग किया है, दस ही रूपया मान लीजिए और जितना आपको सरेंडर करना होगा कीजियेगा, दस रूपया वाला तो बात मान लीजिए, यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री मुजाहिद आलम ।

श्री मुजाहिद आलम : सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 34,798 करोड़ से अधिक राशि की जो बजट अनुदान मांग पेश की गयी है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । शिक्षा, एजुकेशन, Education is the most powerful weapon to change the society, to change the world और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस बात को समझा, इस बात को महसूस किया और जब वे 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाले तो उसके बाद से उन्होंने अनेकों ऐसी योजनायें, ऐसे कार्यक्रम की शुरूआत की जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा कदम है । 2005 में जब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गद्दी संभाली, उस वक्त साढ़े 12 फिसदी बच्चे स्कूलों से बाहर थे लेकिन उनके कोशिशों से जैसे मुख्यमंत्री साईकिल योजना एक स्कीम है, इस योजना की चर्चा पूरे देश ही नहीं, पूरे विदेशों में

इस स्कीम की चर्चा हुई, जिसके तहत 9वीं कक्षा में पढनेवाले छात्र/छात्राओं को 2500 रूपये दिये जाते थे जो अब बढ़कर 3000 रूपये कर दिये गये हैं । यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ और इसके अलावे मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, बालिकाओं के लिए सेनिटरी, नेपकिन योजना हैं । जो हाई स्कूल थे वह पहले जो दस-दस किलोमीटर में थे, मैं खुद अपने जिले की बात कह रहा हूँ, किशनगंज जिला में मात्र 17 हाई स्कूल थे लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार की कोशिश से आज हमारे किशनगंज जिले में 113 हाई स्कूल हैं और जो भी हाई स्कूल बचे हुए पंचायत में, जहां पर हाई स्कूल नहीं है, फरवरी, 2020 से वहां पर इनफास्ट्रक्चर डेवलप करके 9वीं की पढाई शुरू हो रही है और सरकार ने पहले जमीन का जो क्रेटेरिया था, उसमें था कि एक एकड़ जमीन लगेगा, अब उसको भी कम करके 75 डिसमिल कर दिया गया है । मैं पूर्णियां प्रमंडल से आता हूँ, पूर्णियां प्रमंडल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी लेकिन आज दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अल-करीम यूनिवर्सिटी, कटिहार, माता गुजरी यूनिवर्सिटी, किशनगंज और पूर्णियां यूनिवर्सिटी जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, चौथा यूनिवर्सिटी जो प्रोसेस में है, विभाग में लंबित है किशनगंज एजुकेशन ट्रस्ट तो जहां एक भी यूनिवर्सिटी नहीं था, वहां चार-चार यूनिवर्सिटी पूर्णियां प्रमंडल में होने जा रहा है । सरकार ने सात निश्चय के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़े, अवसर बढ़े के तहत कई कार्यक्रम चलाये गये- जैसे स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के तहत जो भी गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको चार लाख रूपये तक बिहार सरकार जो शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उसको कर्ज देने का काम कर रही है और इस वित्तीय वर्ष में अबतक 43,336 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है । इसी के तहत, युवा कुशल कार्यक्रम के तहत हर प्रखंड मुख्यालयों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है । इसके अलावे जो इंटर पास छात्र हैं जो दूसरे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी स्वयं सहायता भत्ता देने का काम किया जा रहा है । हर प्रमंडल में यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, इसके तहत पिछले वर्ष मुंगेर और पूर्णियां में यूनिविर्सिटी की शुरूआत हो चुकी है । हर प्रमंडल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है । पूर्णियां प्रमंडल में भी शिलान्यास हो चुका है । हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, ए0एन0एम0कॉलेज, पॉलिटेकनिक कॉलेज, महिला आई0टी0आई0 सहित सारे इन्स्टीच्यूशन खोले जा रहे हैं ताकि बिहार के जो युवा हैं, वे अपने जिले में, अपने प्रमंडल में उच्च शिक्षा हासिल कर सकें । इसके अलावे और बहुत सारी योजनायें, कार्यक्रम चल रहे हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए है । जो सच्चर कमिटी की रिपोर्ट आयी, उसमें कहा गया कि जो पूरे देश में जो अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों की शिक्षा में जो स्थिति है, वह एस0सी0,एस0टी0 से भी बदतर है । इसको

देखते हुए हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कई कार्यक्रम बिहार में, अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गये और आप जानते हैं कि इससे पहले पूरे बिहार में सिर्फ 1128 सरकारी मदरसे थे लेकिन 2010 में नीतीश कुमार ने घोषणा की कि हम 2459 + A केटेगरी के मदरसों को भी सरकारी अनुदान की श्रेणी में लायेंगे और उन्होंने 205 + 609 , अब तक 814 मदरसों को सरकार के अनुदान की श्रेणी में लाया गया है । शिक्षा मंत्री यहां मौजूद हैं, प्रधान सचिव भी विभाग के हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस 2459 +A केटेगरी के मदरसों में से 475 का फाईल शिक्षा विभाग में लंबित है । उन लोगों से आग्रह होगा कि आप इन मदरसों की जल्द स्वीकृति देने का काम करेंगे। अल्पसंख्यकों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए हर जिले में जैसे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है, इसके तहत 100 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को 9वीं से लेकर 12वीं तक मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया जाय, उसका रहना, खाना, ड्रेस वगैरह सब कुछ देने का काम सरकार करेगी । मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत मदरसों में भवन निर्माण, इनफास्ट्रक्चर निर्माण, बेंच, डेस्क, चहारदिवारी, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था, शौचालय के लिए भी राज्य सरकार ने योजना चलाने का काम किया है।

...क्रमशः....

टर्न-15/राजेश/5.7.19

श्री मुजाहिद आलम : क्रमशः... इसके अलावे मैं आग्रह करुंगा कि 2459+1 के अलावे 339 मदरसें ऐसे हैं जो सरकार के शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-1090 कि सारी शर्तों को ये पूरा करते हैं लेकिन मदरसा बोर्ड की गलती के कारण इन मदरसों को उस सूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि इन मदरसों की जांच विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की गयी है, उनका रिर्पोट मदरसा बोर्ड में आ चुका है, मदरसा बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग में भेजा भी गया है लेकिन उसको यह कहकर लौटा दिया गया कि पहले से हमलोग 2459+1 कैटेगिरी के मदरसों को लेंगे, उसके बाद इनपर विचार करेंगे। इसके अलावे आप सभी लोग जानते हैं कि किशनगंज जिला एक अल्पसंख्यक जिला है और माननीय नीतीश जी अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ए0एम0यू0 सेंटर जो केन्द्र की मदद से वहॉं पर खोलने का काम किये 2011 मे, माननीय नीतीश कुमार जी ने 224 एकड़ उसके लिए जमीन भी दिये और फिर माईनरिटी ब्यॉज एण्ड गर्ल्स होस्टल फी में बिहार सरकार देने का काम किया, फिर 2013 में बी0एड0 की पढ़ाई शुरु हुई, फिर 2014 में एम0बी0ए0 की पढ़ाई शुरु हुई लेकिन 31 जनवरी, 2014 को माननीय मुख्यमंत्री और उस समय की यू0पी0ए0 की चेयरपर्सन ने 136 करोड़ की

योजनाओं का वहाँ पर शिलान्यास किया लेकिन उसमें से मात्र 10 करोड़ रुपये ही अभी तक मिली है, जिसके कारण आज वहाँ पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है और इसका नतीजा है कि वहाँ पर ब्यॉज होस्टल और गर्ल्स होस्टल में ही सेंटर चल रहा है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक सभा चुनाव से पहले खुद प्रकाश जावड़ेकर जो एच0आर0डी0 मिनिस्टर थे, उनको खुद पत्र लिखने का काम किया है और आज जो बिहार में उर्दू शिक्षकों की कमी है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, आप जानते हैं कि जो उर्दू ग्रेस वाला मामला है, 12 हजार शिक्षकों का, जिसके लिए आपलोग बहुत ही प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए बिहार सरकार के प्रधान सचिव और अवर सचिव ने पत्रांक-215 दि0 7.2.2019 को केन्द्र सरकार के एच0आर0डी0 मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने का काम किया, फिर इधर पत्रांक-794 दि0 25.6.2019 के द्वारा फिर से उनको रिमाइनडर भेजा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि आप इस मामले में जो केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है, उनसे बात करें और इस मामले को निबटायें । इसके अलावे एक इशू है कि जो 4 हजार उर्दू शिक्षक जो स्पेशल उर्दू टी0ई0टी0 बंगला पास हैं, जो बचे हुए हैं, उसके लिए भी जो विशेष कैंप लगने जा रहा है, उसमें भी सरकार के अवर सचिव जी की एक चिट्ठी है 2342 दि0 15.2.2016, जिसमें कहा गया है कि लड़कियों के 35 प्रतिशत सीट आरक्षित है, वह सीट अगर बच जाती है, तो उसको उसी साल पुरुष से भर दिया जाय और जो 4 हजार सीट जो यहाँ बचे हुए हैं, वह ज्यादातर महिलाओं के लिए खाली है और महिला स्पेशल उर्दू टी0ई0टी0 बंगला में बहुत कम बचे हुए हैं तो मैं विभाग के प्रधान सचिव भी है, विभागीय मंत्री भी है, मैं उनसे आग्रह करुंगा कि इसमें आप विचार करेंगे ताकि जो बच्चे स्पेशल उर्दू बंगला टी0ई0टी0 पास हैं, उनका नियोजन हो सके । इसके अलावे ....(व्यवधान)

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार):अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री मोजाहिद आलम: सभापति महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्रवण बाबू जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपलोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार):माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र राम ।

श्री शिवचन्द्र राम: माननीय सभापति महोदय, आज बिहार में जो सबसे बड़ा स्तंभ है शिक्षा का जो विकास का जो सबसे बड़ी कड़ी है..............(व्यवधान)

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार):आपका समय कम हो गया है सिद्दिकी साहब की वजह से तो आपलोग पॉच-पॉच मिनट तीनों आदमी बोल लीजियेगा ।

श्री शिवचन्द्र राम: कैसे होगा महोदय । तो मैं कह रहा था महोदय कि जो कड़ी है तो उस कड़ी के हिसाब से सबसे बड़ी प्राथमिक विद्यालय है । निश्चित रुप से अभी सभी साथी ने एक-एक करके अपने विचारों को रखने का काम किया है । सभापति महोदय, आज बिहार की जो हालत बनी हुई है, वह गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, दबे, कुचले, शोषित का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पहला वह अपना स्टार्टिंग करता है और उस विद्यालय का जो भवन है उस भवन पर सभापति महोदय किसी का ध्यान नहीं जा रहा है । सभापति महोदय, आज भी बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं । पहले सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उस विद्यालय को मरम्मति करने के लिए, उस विद्यालय को बनाने के लिए पैसा दिया जाता था और आज इस सरकार की तरफ से इस बजट में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है कि प्राथमिक विद्यालयों को हम मरम्मति कराने का काम करेंगे या इसको बनाने का काम करेंगे और उसका छत जिस समय सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बना था, वह उसीतरह है और आज वह सारा गिर रहा है । सभापति महोदय, मैं इस सदन में एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, हमारे वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड की मैं बात करता हूँ । राजापाकर प्रखंड के राजापाकर प्राथमिक विद्यालय आज वह झर-झर कर गिर रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है । भलुई प्राथमिक विद्यालय का वही हाल है, बॉकापुर प्राथमिक विद्यालय का भी वही हाल है, नारायणपुर प्राथमिक विद्यालय का वही हाल है, साथ ही साथ सदर प्रखंड दरभंगा, उर्दू प्राथमिक विद्यालय जो अदलपुर में है, उसकी स्थिति भी वही है, डिबरई उर्दू स्कूल जो सदर प्रखंड दरभंगा में है, उसकी भी स्थिति इसी तरीके का है, उसके छत गिर रहे हैं, उसके बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, किसी के दरवाजे के पास जा कर पढ़ रहे हैं, जब बारिश आता है, तब वह बोरा या कपड़ा वगैरह लेकर दूसरे के दरवाजा पर चला जाता है और वहॉ जब जाता है तो दरवाजा वाला भी उन सबों को हटा देने का काम करता है, यह हाल तो शिक्षा की बनी हुई है । इसलिए मैं सभापति महोदय, आगे हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि अभी तक इंटर में नामांकन की व्यवस्था आपने किया, जिसको आपने दिया है कि इंटर में ऑनलाईन जो है फॉर्म भरने के लिए 16 स्कूलों को दिया गया है नामांकन करने के लिए, इन 16 का जो किया गया है, उसमें तो कम से कम प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि उसमें बगल में नहीं दे करके और वह स्कूल जो है कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी वाला स्कूल को चिन्हित कर दिया जाता है और ऑनलाईन करने पर लड़का को 400/- रुपया लगता है, उसमें भी वह 10 किलोमीटर से बाजार जाता है और बाजार से जब वह वहॉ आता है तो कहता है कि सर्वर डाउन है, फिर वहॉ से 20 किलोमीटर वह शहर जाता है, तो वहॉ भी कहता है कि सर्वर डाउन है, तो इससे भी आगे चल करके पटना जब चला आता है तो यहॉ भी

कहता है कि सर्वर डाउन है, ऐसी परिस्थिति में सभापति महोदय, आप समझ सकते हैं कि गरीब का लड़का कैसे पढ़ सकता है, उस लड़का को आने जाने में ही 400/- रुपया लग जाता है और उसमें भी काम नहीं होता है और साथ ही साथ अगर हो भी गया, तो 400/- रुपया उसे लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस गरीब का लड़का का न तो नामांकन होगा और न ही वह पढ़ पायेगा, यह सरकार की नीति केवल भाषण की नीति है, कागज पर केवल बजट की नीति है, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगा, बच्चे कैसे डेवलप करेंगे, बच्चे आगे कैसे बढ़ेगें, यह इनका नीति नहीं है । अब ये कह रहे हैं कि हमारा जो गुणवत्ता है, हमारा शिक्षा में सुधार हो, तो यह कैसे हो सकता है । महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि दो तरह की नीतियॉं आपकी चल रही हैं, आपके नियोजित शिक्षक हैं, आप उसको कितना दे रहे हैं, आप तो उसको 15 से 20 हजार रुपया ही वेतन दे रहे हैं और उसी विद्यालय में, हम बधाई देना चाहते हैं माननीय लालू प्रसाद जी को, जिनके शासनकाल में जो बी0पी0एस0सी0 से जो शिक्षक बहाल हुआ, आज वह उसी विद्यालय में नीतीश कुमार जी की कृपा से जो शिक्षक बहाल हुए उनको 20 हजार रुपये मिलता है और उसी विद्यालय में लालू प्रसाद जी के आर्शीवाद से जो शिक्षक बहाल हुआ, उसको वहॉं पर 70 से 80 हजार रुपया मिलता है, तो आप किसतरह का गुणवत्ता चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, कोई पेट काटकर कुछ नहीं कर सकता । इसलिए सभापति महोदय, हमारा यह कहना है कि इसमें बहुत तरह की बातें हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्थितियॉं बनी हैं, वह कहा गया है कि जब तक शिक्षा का विकास के लिए हमारा आपस में समझौता नहीं होगा, जब तक हमलोग एक मत नहीं होंगे, तो आगे हमारा शिक्षा बढ़ नहीं सकता ।

सभापति महोदय, हमारे यहॉं एक कस्तूरबा विद्यालय का मामला है । आज कस्तूरबा विद्यालय की स्थिति यह बन गयी है कि आज वह लूट खसोट का अड्डा बन गया है । आप कस्तूरबा विद्यालय में बच्चों को रहने और खाने की व्यवस्था करते हैं । हमारे वैशाली जिला में हमारा जो संभाग प्रभारी है वह संतोषी डैनी है, वह समझ लीजिये कि वह लगभग छ: साल से वहीं पद पर बैठी हुई है और वह सिर्फ वार्डन से पैसा तसीलने का काम करती है और उसमें जो अच्छा खाना की व्यवस्था का मिनू है, उसके हिसाब से वह वहॉं पर काम नहीं करती है ।

क्रमशः

टर्न-16/सत्येन्द्र/5-7-19

श्री शिवचन्द्र राम (क्रमशः): साथ-साथ हमारे विधान-सभा राजापाकर के हाईस्कूल में जो पैसा दिया गया था 25 हजार रू0, उसमें से भी 6 हजार रू0 को वापस कर लिया गया है,

उसका बिल्डिंग बनकर तैयार है लेकिन और उसमें कोई काम नहीं हुआ है, किबाड़ बगैरह कुछ नहीं बना है तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कैसे विकास होगा ? आज के समय में जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है, ये जो है सभी घूस का आलम बना हुआ है शिक्षा विभाग में, जो बोले हैं सिद्दिकी साहब कि बिना पैसा का काम नहीं होता है, यह पूरी जगहों पर है । महोदय, हमारे वैशाली जिला में एक मनोज कुमार जी हैं जो पन्द्रह साल से उसी जिला कार्यालय में बैठे हैं, ट्रांसफर हुआ लेकिन फिर वे ट्रांसफर करा कर के वहीं चले आये और वे कहते हैं कि हम यहीं चले आये हैं। उसी तरह से बेंक्टेश कुमार, शंभु कुमार और उमाशंकर प्रसाद हैं, ये आपके पटना शिक्षा कार्यालय की मैं बात कर रहा हूँ ये लोग अभी यहां 9 वर्षों से बैठे हुए हैं। कैसे काम चलेगा, इनका जो है कहना है इनके यहां शिक्षा विभाग में माल लाओ, लगाओ और माल पाओ की नीति चल रही है तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहां जो राजापाकर उच्च विद्यालय है, कर्णपूरा उच्च विद्यालय, बांकापुर उच्च विद्यालय, दामोदरपुर उच्च विद्यालय, तोईमठ उच्च विद्यालय है, ये तमाम जगहों पर बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है और बिल्डिंग है भी तो थोड़ा सा पैसा के चलते वह बिल्डिंग जर्जर बना हुआ है इसलिए सभापति महोदय, हम मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि कम से कम इस बिल्डिंग को बनवा देने का काम करें ।

सभापतिः (डॉ0 अशोक कुमार) अब आप समाप्त करें ।

श्री शिवचन्द्र रामः और जो शिक्षक के बीच भिन्नता आ गयी है, उस भिन्नता को दूर करें, सबको बराबर पैसा मिले इसीलिए कहा गया है कि फेंक दो उस पत्थर को...

श्री सुदामा प्रसाद सभापति महोदय, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया है । महोदय, हमारे विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत सहार में एक कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय है और उस कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय में महोदय, 600 छात्राएं हैं और उस कन्या विद्यालय का भवन जर्जर है और छात्राओं ने जब सड़क पर स्कूल लगाया तो उन्हें मॉडल स्कूल में ट्रांसफर किया गया । वहां 600 छात्राओं पर महोदय एक शिक्षक हैं, हम 2016-17 के बजट सत्र में भी इस समस्या का जिक्र कर चुके हैं लेकिन

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

कोई समाधान नहीं निकला, 600 छात्राओं पर एक शिक्षक। महोदय, वर्ष 2000 में आरा जिला में ओ0बी0सी0 छात्रों के लिए एक हॉस्टल बना लेकिन आजतक छात्रों को आवंटित नहीं किया गया और अब वह जर्जर हो गया है, गिरने के पोजिशन में हो गया है इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है । ये आईना है दोनों उदाहरण महोदय, बिहार में प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यायों तक में शिक्षकों और कर्मचारियों के 60 प्रतिशत पद खाली है, जबतक आप उसे भरियेगा नहीं और शिक्षकों

को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दीजियेगा तबतक बिहार के शिक्षा में कोई बदलाव नहीं हो सकता है इसलिए सरकार से मैं यह मांग करता हूॅ कि खाली पदों को तत्काल भरा जाय और शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाय । महोदय, बी0एड0 की पढ़ाई के लिए 95 हजार की फीस थी लेकिन उसे बढ़ाकर के डेढ़ लाख कर दिया गया अचानक, अब गरीब छात्र कैसे पढ़ेंगे इसलिए इस बढ़ी हुई फीस की भी वापसी की मैं मांग करता हूॅ और अब आया जाय वन विभाग पर, मैं एक बात रखना चाहता हूॅ कि जो वन अधिकार कानून, 2006 है..

अध्यक्ष: कितना अच्छा तो शिक्षा पर बोल रहे थे तो जंगल में कहां जा रहे है ?

श्री सुदामा प्रसाद: नहीं, यह भी आज है और बहुत जरूरी है महोदय, आज ही 6 थारू आदिवासी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है । वे खेत पर गये थे अपना हल बैल लेकर के, बगहा प्रखंड-2 उसमें एक गांव है आपको गुमवाटांड वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया और लोग जब पूछने के लिए गये कि वे कहां है, यह महोदय, आज सुबह की ही बात है तो रेंजर ने कहा कि पटना से टीम आयी थी कहां लेकर गयी पता नहीं, तो 2006 का जो कानून है जिसके तहत जंगली क्षेत्र में जो 10 साल से आदिवासी रह रहे हैं और जो गैर आदिवासी 30 साल से रह रहे हैं, 30 एकड़ तक की सीमा में उनको जमीन का परवाना देना था, जंगली उत्पाद पर उनको अधिकार देना था, फल तोड़ने का, केन्दु पत्ता तोड़ने का, जानवर चराने का, मछली मारने का, वहां स्कूल खोलने की बात थी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए वहां स्कूल खोलना था, पानी की टंकी बैठानी थी वहां पर जो है बिजली ले जाना था लेकिन इन कामों को करने के बजाय आदिवासियों को वहां से उजाड़ा जा रहा है और जंगल खाली कराया जा रहा है । महोदय, जल संरक्षण पर बात हो रही थी उसी जंगल आदिवासी लोगों पर जंगल की सुरक्षा है इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूॅ कि वन कानून, 2006 को सख्ती से यहां लागू किया जाय ताकि आदिवासी जनता के अधिकारों की रक्षा हो । धन्यवाद ।

श्री रत्नेश सादा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज शिक्षा विभाग के बजट भाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूॅ । महोदय, शिक्षा वह तलवार है जो अंधकार रूपी विशाल वृक्ष को काटकर के समाज में फैले व्याप्त अशिक्षा को समाप्त करती है और शिक्षा गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत बड़ा हथियार है । अगर शिक्षा नहीं होती तो मैं आज यहां नहीं आता, शिक्षा के बल पर ही मैं आज आपके सामने विधान-सभा में बोल रहा हूॅ शिक्षा के महत्व पर, महोदय, आदिम काल से ही शिक्षा के लिए बड़े बड़े राजाओं के पुत्र जंगल में जाकर गुरूकुल में सब तरह की शिक्षा प्राप्त करते थे । विद्या हो, आयुर्विद्या हो, जो तरह की विद्या होती थी वह सब प्राप्त करते थे । शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है महोदय, जब राम को धन विद्या की जरूरत पड़ी तो उनको भी जंगल

जाना पड़ा और विश्वामित्र उनके गुरू बने थे । कृष्ण को भी ज्ञान की जब जरूरत पड़ी तो उनको भी जाना पड़ा संदिपनी मुनि के पास, महोदय, उसी प्रकार एकलव्य को गुरू द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर के शिक्षा ग्रहण करना पड़ा । महोदय, उसी तरह बाल्मिकी जी भी जो रत्नाकार पहले थे उनको भी नारद से शिक्षा प्राप्त करना पड़ा था । महोदय, उसी तरह आज नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, लोक शिक्षक हैं । इस बात पर थोड़ा गौर कीजियेगा, वह लोक शिक्षक हैं इसलिए कि समाज में जिस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता था, जिस समाज में किसी तरह की शिक्षा नाम की कोई रोशनी नहीं थी उस समाज को अलख जगाने के लिए नीतीश कुमार लोक शिक्षक के रूप में बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं । महोदय, समझने की कोशिश कीजिये, शिक्षा का महत्व क्या है बरदराज जब गुरूकुल गये थे तो उनको कोई ज्ञान की समझ नहीं होती थी, समझ नहीं आता था तो गुरूकुल से उसको निकाल दिया गया था लेकिन जब बरदराज रास्ते में आये और प्यास लगा और कुआं के पास गया तो रस्सी का निशान था, करत करत अभ्यास को जनमत हो सुजान, रसरी या ब जात है सिर पर परत निशान, आज बरदराज को निकाला और जब अभ्यास किया तो उन्होंने मेघदूत लिख दिया, वह शिक्षा है, ये वह शेरनी का दूध है जिसको पीने से इतना शक्ति पैदा होता है कि आजीवन सुखमय जीवन व्यतीत करता है इंसान । शिक्षा प्राप्त करने से शिष्टाचार जीवन निर्मल होता है । महोदय, इसलिए मैं संस्कृत में पढ़ा था कि शिक्षा का महत्व क्या है कि

विद्वत्वं च नृपत्वं च न एव तुल्ये कदाचन ।
राजा स्वदेशे पूज्यते विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ।।
माता शत्रु पिता वैरी, ऐन बालकों न पाठ्यते,
न शोभते मद हंस वक्याथा,
लागते पंचवर्षानी दसवर्षानी ताजते,
प्राप्तेषु सम वर्षम पुत्रम निश्रम वदाचरते । (क्रमशः)

टर्न-17/मधुप/05.7.2019

...क्रमशः...

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, विद्या वह है, जो विद्वान होते हैं उसकी पूजा पूरे विश्व में होती है लेकिन राजा की पूजा उनके राज्य भर में होती है । जैसे- जो मॉ-बाप अपने बाल-बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है । जैसे- हंस के बीच बगुला शोभा नहीं देता है, हंस में वह गुण होता है कि दूध से पानी को अलग कर देता है लेकिन बगुला में वह शक्ति नहीं है । उसी प्रकार शिक्षा विहीन मनुष्य पशु के समान होता है ।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐप के माध्यम से...

अध्यक्ष : अब एक मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री रत्नेश सादा : ऐप के माध्यम से 45628 प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया...

(व्यवधान)

महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा में 2019-20 में व्यय के लिए 347 अरब 98 करोड़ 669 लाख 44 हजार रू0 की व्यवस्था की है । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शिक्षा विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्रीमती समता देवी । 3-4 मिनट में अपनी बात कह लीजिये ।

श्रीमती समता देवी : अध्यक्ष महोदय, आज मैं शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, मैं शिक्षा के महत्व के बारे में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा हमलोगों के लिए बहुत मायने रखती है । बिना शिक्षा के कुछ नहीं कर सकते हैं । शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके सहारे के बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है । शिक्षा एक अनमोल धन है जिसे खरीदा नहीं जा सकता है । बजट का शिक्षा पर 40 प्रतिशत व्यय होता है और बिहार में शिक्षा का क्या हाल है । आये दिन दिन-प्रतिदिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । महोदय, लालू जी के बारे में बार-बार सत्ताधारी दल के लोग बोलते हैं कि लालू जी सरकार में चरवाहा विद्यालय खोला गया था, उस विद्यालय में गरीब एवं किसान के बच्चे शिक्षा ग्रहण किया करते थे परंतु वर्त्तमान सरकार में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है । यह हमलोग भली-भाँति जानते हैं । यह एक शोध का विषय बन चुका है कि जबतक शिक्षा में भेदभाव अमीर-गरीब का मिटाया नहीं जायेगा तबतक शिक्षा का समान अवसर नहीं मिल सकता है ।

महोदय, हमारे बिहार राज्य के अमीर परिवार के बच्चे उच्च स्तर की शिक्षा पाने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं वहीं गरीब एवं किसान के बच्चों के माँ-बाप के पास उतना पैसा नहीं है कि बाहर जाकर पढ़ सकें । अगर सरकार के द्वारा दूसरे राज्यों के जैसा बिहार में भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करा दिया जाता है तो उम्मीद है कि हमारे गरीब के बाल-बच्चे को भी बी0डी0ओ0, सी0ओ0, डॉक्टर, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 बनने का अवसर मिल सकता है ।

महोदय, अभी हाई स्कूल को 10+2 में उत्क्रमित किया गया है, उसमें शिक्षा का काफी अभाव है । महोदय, सरकार का कहना है कि बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि गया जिला के अन्तर्गत बाराचट्टी विधान सभा क्षेत्र में एक भी महिला कॉलेज नहीं है । हमारी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाराचट्टी से करीब 50 कि0मी0 दूरी तय करके गया जाना पड़ता है । आप समझ सकते हैं कि बेटियों को रोज आने-जाने में कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती होगी । इसलिए मैं वर्त्तमान

सरकार से इस बिन्दु की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि बाराचट्टी विधान सभा क्षेत्र में महिला कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की कार्रवाई की जाय ।

महोदय, बाल विकास परियोजना में जो भी सेन्टर सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसमें समय से बच्चों का पोषाहार नहीं मिल पाता है । अगर मिलता भी है तो कटौती कर दिया जाता है । बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के बारे में सभी लोग वाकिफ हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है । मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सुदय जी, आप बोलेंगे क्या 2 मिनट ? 2 मिनट बोल लीजिये । एकदम 2 मिनट में अपनी बात कह डालिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, मैं अपने पिता मुन्द्रिका सिंह यादव जी को स्मरण करते हुए, अपने नेता और सदन के आसन को धन्यवाद देते हैं कि शिक्षा के बजट पर जो विपक्ष के द्वारा कटौती-प्रस्ताव दिया गया है, उसके पक्ष में बोलने का मौका मिला है।

अध्यक्ष महोदय, आज जो शिक्षा की हालत है, सत्तापक्ष के कई विधायक, हम उनके समर्थन में, जैसे- जितेन्द्र भाई ने जो सवाल उठाया था, हम उसके पक्ष में हैं। जिस तरह रंग-रोगन करके शिक्षा विभाग में विद्यालय बनाया गया है वह सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए है । आज बच्चे उस विद्यालय में जा नहीं रहे हैं । यह सौभाग्य हमारा प्राप्त है कि हमारे ही जिला से शिक्षा मंत्री जी आते हैं लेकिन जो हालत है, हमारे जिला के शिक्षा का और खास करके एक और ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं, चूंकि दो मिनट का समय है, वहाँ गाँधी स्मारक इण्टर विद्यालय है, उसके पास हम समझते हैं कि करीब 10 एकड़ से ज्यादा जमीन थी लेकिन भू-माफियाओं द्वारा उस जमीन को काफी कब्जा करके बेच दिया गया है । इस सवाल को मेरे पिताजी भी इस सदन में उठाये थे लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार वहाँ के प्राचार्य के भी द्वारा, उनपर कई तरह के आरोप भी हैं गबन के, इसके बावजूद भी उसमें पदस्थापित हैं । हम सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से माँग करेंगे ।

हमारे जिला में खास करके जो हाई स्कूल की जो दुर्दशा है, कई हाई स्कूलों में चहारदिवारी नहीं है और जो सबसे महत्वपूर्ण अभी शिवचन्द्र राम जी ने जो बात कही कि इण्टर के नामांकन में ऑनलाईन जो आवेदन दिया जा रहा है और दूसरे जिला में

उसके नामांकन के लिए उसको मार्किंग किया जा रहा है, यह बहुत गम्भीर विषय है। समाज के अंतिम पायदान के लोगों के घर से जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनके पास सबसे बड़ी चुनौती है, सरकार इन सवालों को लेकर गम्भीर हो और गम्भीर होकर इसको ध्यान में रखे ।

एक मिनट, हम एक बात और आग्रह करेंगे कि चूंकि हमारे पिता शिक्षाविद् रहे थे और जिस स्कूल में, करपी उच्च विद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, हम चाहते हैं सरकार के द्वारा उनके नाम से उस स्कूल का नामाकरण किया जाय । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा विभाग की माँग पर कुल 12 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, इनमें से कई लोगों के विचार और सुझाव अच्छे थे और कुछ के तो बहुत अच्छे थे । मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ ।

एक बात मेरे बताये बगैर भी आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है और शिक्षा में तो जो विकास हुआ है वह हमसे ज्यादा आप भी बोलते हैं कहीं-कहीं पर लेकिन तन्हाई में बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं । ...क्रमश।ः....

टर्न-18/शंभु/05.07.19

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : क्रमशः.. माननीय नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले ग्राउन्ड लेवेल पर जो स्थिति थी उसको देखा । क्या स्थिति थी- गरीब गुरबा के बच्चे, महादलित के बच्चे, माइनोरिटी के बच्चे ये सब स्कूल के बाहर थे, नहीं आते थे स्कूल में और उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कई योजनाएं चलायी- खासकर के तालीमी मरकज और टोला सेवक । उन लोगों की मेहनत से माननीय मुख्यमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं के चलते लोगों में आकर्षण बढ़ा । आज स्थिति यह है कि 99 प्रतिशत बच्चे स्कूल के अंदर आ गये और उसकी पढ़ाई की व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। शिक्षा के मामले पर सबलोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से इसको लिया-शुरू से ही युद्ध स्तर पर अन्य विभागों के साथ-साथ इस विभाग पर इनका

फोकस ज्यादा रहा तो विकास के मामले में और शिक्षा के विकास के मामले में

तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं,
तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं,
कैसे मिलता कोई था ही नहीं ।

अध्यक्ष : वाह । ललित जी, आप मिस कर गये न । हम देख रहे थे आप मिस कर गये । मंत्री जी फिर से सुना दीजिए, कुछ लोग मिस कर गये हैं ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : बहरहाल मैं आगे भी आपको सुनाऊंगा ।

(व्यवधान)

आज जाने की जिद न करो ।
यूं ही पहलू में बैठे रहो,
आज जाने की जिद न करो।

अध्यक्ष : आज मंत्री जी, गद्य में बोलेंगे ही नहीं ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं कहीं भी जाता हूँ क्षेत्र में तो अपनी तकरीर में इस बात की चर्चा जरूर करता हूँ कि भाई तनहाई में जब आप रात में सोने जाएं तो एक मिनट के लिए आंख बन्द करके सोचें कि आपके गांव में जिस व्यक्ति, जिस परिवार में संपन्नता आई उसकी वजह क्या थी । आप जब उसकी वजह ढूढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि संपन्नता आने के साथ जब वहां पहले शिक्षा आई तब संपन्नता आई इसलिए आज आपने इरादों को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए सभी लोगों की पढ़ाई आवश्यक है । शिक्षा में ही वह ताकत है, शिक्षा में ही वह शक्ति है कि गरीब मजदूर हो, ठेलावाला हो, रिक्शा चलानेवाला हो, सब्जी बेचनेवाला हो उसका बेटा और बेटी भी आइ0ए0एस0 बन सकता है । यह ताकत केवल शिक्षा में है । इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे बिहार ने एक्सेप्ट किया और जैसा मैंने कहा कि गरीबों के बच्चों को स्कूल पहुंचाना हमारी प्राथमिकता थी और स्कूल जब पहुंच गया टोला सेवक या तालीमी मरकज के वजह से या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं की वजह से तो वहां उसको शिक्षा मिलने लगी । आज कई सदस्यों ने इसकी चर्चा की है शिक्षकों की कमी का मैं मानता हूँ कि अभी कुछ कमियां हैं चूंकि हमलोग उत्क्रमित करते चले जा रहे हैं पंचायतों में प्लस टू, हाईस्कूल और प्लस टू करने का जो हमलोगों की घोषणा है और इरादा है उसपर काम कर रहे हैं तो मुनासिब है कि हमको जरूरत पड़ेगी । आपको पता होगा कि बिहार में एक इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिया गया जो शायद अन्य राज्यों में इस तरह के फैसले नहीं लिये जाते हैं । यहां टी0इ0टी0 और एस0टी0इ0टी0 पास काफी अभ्यर्थी थे, नौजवान थे और उनका वक्त पूरा हो गया था, उनके सर्टिफिकेट की मान्यता समाप्त हो रही थी और वह

समाप्त होने के बाद उनको नौकरी की दुश्वारी हो जाती, मुश्किल होती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और इन्होंने सही चीज को पकड़ लिया । इन्होंने कहा कि अगर उसकी अवधि खत्म हुई इसलिए क्योंकि मामला आप कोर्ट में ले गये थे और डेढ़ वर्षों तक उसमें मामला उलझा रहा इसमें उसका क्या दोष है ? नेचुरल जस्टिस का तकाजा है कि उनकी अवधि को बढ़ा दी जाय । यह बहुत बड़ी बात हुई और इतना ही नहीं हम उन सब लोगों को शिक्षक बनाने का इरादा रखते हैं-नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, शेड्यूल तैयार हो गया है और प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में हम बहुत जल्द उन लोगों को अवसर देने जा रहे हैं तो ये इस तरह का एक क्रांतिकारी फैसला लिया गया । आज जो आप शिक्षकों की कमी की चर्चा करते हैं उसको हमलोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं । एक बात और बिहार में होने जा रहा है शिक्षा के मामले में जिसको आप जानना चाहेंगे कि माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लागू नवाचार उन्नयन बांका की सफलता को देखते हुए बिहार के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में सूचना टेक्नोलॉजी का उपयोग कर शैक्षणिक वातावरण में सुधार की कार्रवाई के उद्देश्य से उन्नयन बिहार अगस्त, 2019 से प्रारंभ किया जा रहा है । ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के और आप इसको देखेंगे और इसकी बहुत सराहना करेंगे । शिक्षा को हम बहुत सुलभ बनाने जा रहे हैं ताकि गरीब के बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण करें । एक चीज अकसर हम भी जाते थे, आप भी जाते होंगे गांव में तो लोग बोलते थे कि भाई हमलोग अपने बच्चों को हाईस्कूल तक, इंटर तक तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन हम उच्च शिक्षा में नहीं पढ़ा पाते, टेक्नीकल एजुकेशन भी हम नहीं दे सकते हैं चूंकि हमारी माली हालत ठीक नहीं है, हमारी सलाहियत नहीं है । अब यह कितनी बड़ी है कि इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और चुनाव के दौरान इन्होंने घोषणा किया था कि हम जब सरकार में आयेंगे तो 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे । यह इनका वादा- वादा नहीं जमीन पर उतरनेवाला वादा हुआ और इसको इन्होंने पूरा करके दिखाया । आज गरीब परिवार के बच्चे भी हौसला रखते हैं उनका हौसला बढ़ा है । वे लोग भी आगे की शिक्षा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं । इस मामले में 2018-19 में कुल 43 हजार 336 विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया है । इसके तहत 1157 करोड़ 24 लाख रूपये स्वीकृत राशि से 34999 छात्र-छात्राओं को 307 करोड़ 43 हजार रूपये वितरित किये जा चुके हैं । इसमें एक मुश्किलात थी पहले कि इसको बैंक के जरिये दिया जाता था और वहां हमारे छात्रों को बहुत परेशानी होती थी, तंग किया जाता था- माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कैबिनेट की बैठक में कि इसके बारे में हमलोगों को कुछ सोचना चाहिए, सचमुच में उन लोगों को परेशान किया जाता है । उसके वितरण

की रफ्तार कम थी लिहाजा इन्होंने उसमें सुधार करके विभाग में ही शिक्षा ऋण की व्यवस्था की और वहां से उनको ऋण आसानी से मिल रहा है । बहुत सारी बातें हैं सबकी चर्चा करना इतना मुख्तसर वक्त में मुमकिन भी नहीं लगता है फिर भी मैं बताना चाहूंगा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पद पर नियोजन की कार्रवाई माह जुलाई, 2019 से प्रारंभ करते हुए फरवरी, 2020 तक विभिन्न चरणों में पूर्ण करने के लिए हम काम कर रहे हैं । मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना इसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना मद से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग के कोटि के 39023 छात्राओं के लिए प्रति छात्रा 10 हजार रूपये की दर से राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है । अध्यक्ष महोदय, सरकार की प्राथमिकता है हमलोग अपना वक्त, अपना जमाना याद करते हैं....क्रमशः।

टर्न-19/ज्योति/05-07-2019

क्रमशः

श्री कृष्ण नंदन वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार की प्राथमिकता है । हमलोग अपना वक्त जमाना याद करते हैं जब हमलोग गांव में पढ़ते थे, बाद में पटना आए । एक भी परिवार से कोई लड़की पढ़ने नहीं जाती थी और उनके अभिभावकों की मानसिकता क्या थी । उनकी मानसिकता थी कि बच्चियों को पढ़ाकर क्या करना है, इनको कहाँ नौकरी करनी है । आज वह मानसिकता बदली है माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, आज ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह छात्रों की संख्या से ज्यादा छात्राओं की संख्या है । संख्या ही नहीं बल्कि वे पास भी जयादा संख्या में कर रही हैं और लड़कों से ज्यादा रिजल्ट दे रही है और इसके लिए हमलोगो ने उनको अलग से पुरस्कार देने की भी योजना बनायी है तो यह जो बुनियादी परिवर्तन आया है समाज के अंदर । ....

(व्यवधान)

यह सब हमारा परफौरमेंस है, उसकी चर्चा कर रहे हैं, आपकी बात का भी जवाब दे देंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, सदन के समक्ष आपके लिए प्रस्ताव रखा कि यह सदन जो है आज एक प्रस्ताव ले कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री के समक्ष गुहार की थी पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का तो सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पारित करवा लीजिये, एक प्रस्ताव ले आईये ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : उस पर आयेंगे ।

अध्यक्ष : उस पर आयेंगे, मंत्री जी जो कह रहे हैं उसको सुनिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दकी : दो लाईन हम भी सुना दें आपको ।

श्री कृष्ण नंदन वर्मा,मंत्री : इरशाद ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दकी : ''गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता।''

श्री कृष्णनंदन वर्मा, मंत्री : बहुत बहुत शुक्रिया । कुछ हमने कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। सिदि्दकी साहेब के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा आपकी इजाजत से ।

''कभी तुमको हमसे चाह थी, कभी हमको तुमसे निबाह थी,
कभी भी हम थे सनम, आशना तुझे याद हो कि न याद हो ।''

(व्यवधान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : बोलिए, बोलिए ।

अध्यक्ष : आपलोग अंताक्षरी करियेगा क्या ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दकी : महोदय, मात्र 5 मिनट रह गया है । जिन सवालों को हमलोगों ने उठाया और सत्ता पक्ष ने भी आईना दिखाया उसका ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। न पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहे हैं और न बेसिक स्कूल के बारे में बोल रहे हैं । आप नहीं बोल रहे हैं इसलिए आपका लिखा लिखाया वक्तव्य वितरित किया हुआ उसको पढ़ लिया है और फिर वही चीज दोहरा रहे हैं इसलिए आपकी बात पर बहिष्कार करतें हैं ।

श्री कृष्णनंद प्रसाद वर्मा, मंत्री : आपलोग जाने की जिद न करिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दकी : कम से कम अब बोल तो दीजिये पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

अध्यक्ष : मंत्री जी अपनी बात जारी रखिये । मंत्री जी इधर देखिये । अपनी बात कहिये ।

श्री कृष्णनंद प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, राज्य सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित 13 विश्वविद्यालयों के अलावे 07 निजी विश्वविद्यालयों यथा-अमिटी विश्वविद्यालय, पटना, संदीप विश्वविद्यालय, मधुबनी, के0के0 विश्वविद्यालय, नालन्दा, डा0 सी0वी0रमण विश्वविद्यालय, वैशाली, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार(सासाराम), अल-करीम विश्वविद्यालय, कटिहार एवं माता गुजरी विश्वविद्यालय, किशनगंज की स्थापना की गयी है ।

तकनीकी शिक्षा के लिए बिहार में क्या स्थिति में परिवर्तन आया है , बदलाव आया है शिक्षा के क्षेत्र में उस पर भी आपलोग सुन लेते तो ज्यादा अच्छा होता । तकनीकी शिक्षा के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है । इसमें नैनो सायंस एवं नैनो टेक्नोलॉजी के अध्ययन की व्यवस्था है तथा स्कूल औफ

जर्नलिज्म ऐण्ड मास कौम्यूनिकेशन, पाटलिपुत्र स्कूल औफ इकोनौमिक्स ऐण्ड सेंटर फौर रिवर स्टडीज एवं सेंटर फौर जियोग्रेफिकल स्टडीज के रुप में चार स्वायतशासी उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना की गई है । इस प्रकार बिहार के शैक्षणिक जगत में ठोस और परिणामकारी कार्य करने में हम अग्रसर हैं ।

गांधी जी की चर्चा कर रहे थे आदरणीय सिद्दकी साहेब । गांधी जी के जीवन पर आधारित शिक्षाप्रद कहानियों की दो किताबें '' एक था मोहन' एवं ''बापू की पाती'' तैयार की गई है । प्रतिदिन प्रार्थना के बाद उनमें से एक कहानी पढ़ी जा रही है । इसकी व्यापक सराहना हो रही है । शिक्षक, छात्र सभी इसमें रुचि ले रहे हैं ।

बापू के बारे में जो सिद्दकी साहेब ने कहा पूरा राज्य और देश जानता है कि बापू से जुड़े कार्यक्रम हमलोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक सौ साल से ऊपर हमलोग डेढ़ सौवां साल हमलोग मनाने जा रहे हैं और पूरा वातावरण गांधाी जी के विचारों के अनुरुप राज्य चले, देश चले, इसपर हमलोगों का फोकस है इसलिए मैं सिद्दकी साहेब से कहना चाहूँगा अगर लॉबी से वे सुन रहे होंगे और मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसे कार्यों में आपका सहयोग चाहिए आपका समर्थन चाहिए ।

शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के व्यय वहन हेतु कुल 347 अरब 98 करोड़ 69 लाख 44 हजार रुपये का उपबंध मांग संख्या 21 के अंतर्गत प्रस्तावित है । इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अलावे राज्य स्कीम एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीम शामिल है । इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 144 अरब 89 करोड़ 66 लाख 44 हजार रुपये प्रस्तावित हैं । वार्षिक स्कीम के लिए कुल 203 अरब 9 करोड़ 3 लाख रुपये का प्रस्ताव है इसमें केन्द्र प्रायोजित स्कीम अंतर्गत केन्द्रांश की राशि 82 अरब 14 करोड़ 3 लाख रुपये राज्यांश की राशि 87 अरब 24 करोड़ 90 लाख 24 हजार रुपये, राज्य स्कीम के लिए 32 अरब 20 करोड़ 9 लाख 76 हजार रुपये एवं वाह्य संपोषित परियोजना हेतु एक अरब पचास करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है ।

अध्यक्ष महोदय, अभी सिद्दकी साहेब चर्चा कर रहे थे केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बारे में । मैं उनको जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि दो केन्द्रीय विश्विद्यालय साउथ बिहार, बोध गया में है और महात्मा गांधी, मोतिहारी में है । बिक्रमशीला भागलपुर में प्रस्तावित है । उन्होंने एक बात और कही कि पटना विश्विद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए इस संबंध में हमलोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष ये बातें रखी थी, हमारे मुख्यमंत्रे जी ने इसको रखा था हम समझते हैं कि विचरोपरान्त जब समय आयेगा तो निश्चित रुप से वह भी केन्द्रीय

विश्वविद्यालय बन जायेगा, दर्जा मिल जायेगा । एक बात उनको अभी जानकारी नहीं है उन्होंने कह दिया मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के बारे में कुछ नहीं किया गया । हकीकत यह है कि हमलोगों ने कुछ ही दिन पहले 82 करोड़ रुॅपये की लागत से भवन निर्माण की कार्रवाई प्रारम्भ की है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया और इतने बड़े शख्सियत के नाम पर विश्वविद्यालय भवन बन रहा है मौलाना सहोहब के नाम पर, उसका बहुत जल्द निर्माण हो जायेगा और उसमें काम बहुत तेजी से लगा हुआ है । इसतरह से अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष योजना के रुप में इसको लेकर के और जनहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पर बजट व्यय काफी है । हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे भी इरादे नेक है, हम शिक्षा को बहुत ऊंचाईयों तक ले जाना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा ही एक मात्र साधन है जिससे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं और गरीबों के चेहरे पर लालिमा आ सकती है । आखिर में एक बात कह कर खत्म करुंगा कि

''इल्म की शमां को रौशन जो किया करते हैं,
इल्म की शमा को रौशन जो किया करते हैं,
जिन्दा रहते हैं हमेशा, वो कहां मरते हैं ।''

इसलिए हमारी यह अहमियत है तालीम । एजूकेशन हमारी प्रायरिटी है ।

टर्न-20/05.07.2019/बिपिन

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : (क्रमशः) इसलिए यह हमारी अहमियत है । तालीम, एजुकेशन हमारी प्रायरिटी है और इसपर हम कुछ भी खर्च करने को तैयार हैं ताकि विकसित राज्य का हमारा जो सपना है, वह सपना पूरा हो सके ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह जो कागज है कुछ । इसको प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जो दस्तावेज रख रहे हैं, इनके भाषण का हिस्सा बनेगा।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : इसके साथ ही जो माननीय सदस्य यहां पर हाजिर नहीं हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और बजट को पारित करने की कृपा की जाए ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''इस शीर्षक की मॉंग 10/-रूपए से घटाई जाए ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 347,98,69,44,000/-(तीन सौ सैंतालीस अरब अनठानवे करोड़ उनहत्तर लाख चौवालीस हजार) रूपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 05 जुलाई, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 36 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 08 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा

मंत्री

शिक्षा विभाग

का

मांग संख्या – 21 पर

वक्तव्य

(2019-2020)

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार के चतुर्दिक विकास में शिक्षा को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। हमारी आर्थिक उन्नति, सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। नैतिक बल और चरित्र, शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार सभी वर्गों विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे-बच्चियों के शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है। इनके लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इसमे हमें सफलता भी मिली है।

बिहार में 99% से अधिक बच्चे विद्यालय में नामांकित हो गये हैं। शेष बचे 1% से कम विद्यालय के बाहर के बच्चों को भी विद्यालय में लाने का कार्य चल रहा है। विद्यालयों के निरीक्षण हेतु बेस्ट (Bihar Easy School Tracking) नामक एक मोबाईल एप विकसित किया गया है। इस एप के द्वारा कुल 45,628 प्रारंभिक विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है एवं इस निरीक्षण से शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति में सुधार हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा मुहैया कराने के नीतिगत निर्णय के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय से अनाच्छादित सभी पंचायतों में अप्रैल, 2020 से वर्ग 9 की पढ़ाई का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं।

जिन पंचायतों में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिये मध्य विद्यालय में पर्याप्त भूमि (75 डिसमिल) उपलब्ध नहीं हो सकी है, ऐसे विद्यालयों में वर्ग 9 की पढ़ाई आरंभ करने के लिए

वर्ग कक्ष तैयार करा कर समुचित उपस्कर, शिक्षक की व्यवस्था फरवरी, 2020 तक कर लेने की हमारी योजना है।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पद पर नियोजन की कार्रवाई माह जून, 2019 से प्रारंभ करते हुए फरवरी, 2020 तक विभिन्न चरणों में पूर्ण करना है।

मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2018 में उत्तीर्णता प्राप्त सभी कोटि के अविवाहित छात्राओं को प्रति छात्रा ₹10,000 (दस हजार रूपये) की दर से कुल 2,49,856 छात्राओं के लिए ₹249.86 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2019 के माध्यमिक परीक्षा में 8,22,842 छात्र एवं 8,37,767 छात्राओं ने भाग लिया। छात्राओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मैट्रिक में 83.19% छात्र एवं 76.01% छात्राओं ने उत्तीर्णता हासिल की है। इन्टरमीडिएट में 77.58% छात्र तथा 79.80% छात्राओं ने उत्तीर्णता हासिल की है। आधी आबादी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है।

इसके अलावे मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। बालिका से संबंधित योजनाओं का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, कुल प्रजनन दर में कमी लाना तथा लिंग अनुपात के असमानता को समाप्त करना है। इन सभी उदेश्यों की प्राप्ति में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के क्रम में हुए नवाचार ''उन्नयन बाँका'' की सफलता को देखते हुए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में सूचना टेक्नोलॉजी का उपयोग कर शैक्षणिक वातावरण में सुधार की कार्रवाई के उद्देश्य से इसका विस्तार राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ''उन्नयन बिहार'' के नाम से यह नवाचार अगस्त, 2019 से प्रारंभ किया जा रहा है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था में किये गए महत्त्वपूर्ण तकनीकी बदलावों के परिणामस्वरूप समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं माध्यमिक वार्षिक परीक्षा, 2019 का परीक्षाफल मूल्यांकन प्रारम्भ होने की तिथि से मात्र 28 दिनों के अंदर प्रकाशित किया गया, जो पूरे देश में एक कीर्तिमान है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के संचालन की अधिसूचना निर्गत की गई और यह संस्था संचालित हो चुकी है।

राज्य सरकार के सात निश्चय योजना के तहत् बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत वितीय वर्ष 2018-19 में कुल 43,336 विद्यार्थियों को उच्चत्तर शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया है। 34,999 छात्र-छात्राओं को ₹307.43 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

पूर्व से स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालयों के अलावा 07 निजी विश्वविद्यालयों यथा- अमिटी विश्वविद्यालय, पटना, संदीप विश्वविद्यालय, मधुबनी, के० के० विश्वविद्यालय, नालन्दा, डॉ सी०वी० रमण विश्वविद्यालय, वैशाली, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार (सासाराम), अल-करीम विश्वविद्यालय, कटिहार एवं माता गुजरी विश्वविद्यालय, किशनगंज संचालित हो चुकी है।

तकनीकी शिक्षा के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसके अन्तर्गत नैनो सायंस एवं नैनो टेक्नॉलौजी के अध्ययन की व्यवस्था है तथा "School of Journalism and Mass Communication", "Patliputra School of Economics" and "Centre for River Studies" एवं "Centre for Geographical Studies" के रूप में चार

स्वायत्तशासी उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना की गई है। इस प्रकार बिहार के शैक्षणिक जगत में लगातार ठोस और परिणामकारी कार्य करने में हम अग्रसर हैं।

शिक्षा पर व्यय

(i) शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के व्यय वहन हेतु कुल ₹347,98,69,44,000 (तीन सौ सैतालिस अरब अन्ठानवे करोड़ उन्हत्तर लाख चौवालिस हजार रूपये) का उपबंध मांग संख्या-21 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अलावे राज्य स्कीम एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीम शामिल है।

(ii) इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए ₹144,89,66,44,000 (एक सौ चौवालिस अरब नवासी करोड़ छियासठ लाख चौवालिस हजार रूपये) प्रस्तावित है।

(iii) वार्षिक स्कीम के लिए कुल ₹203,09,03,00,000 (दो सौ तीन अरब नौ करोड़ तीन लाख रूपये) का प्रस्ताव है, जिसमें केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि ₹82,14,03,00,000 (बेरासी अरब चौदह करोड़ तीन लाख रूपये), राज्यांश की राशि ₹87,24,90,24,000 (सतासी अरब चौबीस करोड़ नब्बे लाख चौबीस हजार रूपये), राज्य स्कीम के लिए ₹32,20,09,76,000 (बत्तीस अरब बीस करोड़ नौ लाख छिहत्तर हजार रूपये) एवं वाह्य सम्पोषित परियोजना हेतु ₹1,50,00,00,000 (एक अरब पचास करोड़ रूपये) का बजट प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज सदन के समक्ष मैं शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तावित करने जा रहा हूँ। इस क्रम में सरकार के द्वारा किये गये कुछ उल्लेखनीय कार्य को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

(1) जिन पंचायतों में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिये मध्य विद्यालय में पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी थी, ऐसे विद्यालयों में वर्ग 9 की पढ़ाई आरंभ करने के लिए आवश्यकतानुसार वर्गकक्ष तैयार करा कर समुचित उपस्कर, शिक्षक की व्यवस्था फरवरी, 2020 तक कर लेने की हमारी योजना है। बिहार के सभी पंचायतों में अप्रैल 2020 से हम कक्षा 9 की पढ़ाई आरंभ करने जा रहे हैं।

(2) **TET** 2012 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि मई, 2019 को समाप्त हो चुकी है। लगभग दो वर्षो तक नियोजन की कार्रवाई स्थगित थी। इस पृष्ठभूमि में 2012 में उत्तीर्ण **TET** अभ्यर्थियों के हित में अगले दो वर्ष के लिए वैधता की अवधि विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। फलतः **TET** उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो प्रशिक्षित हैं, उन्हे नियोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

(3) **STET** 2012 उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की अवधि जो जून 2019 में समाप्त हो चुकी है, को भी अगले दो वर्ष के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इन्हें भी आगामी नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

(4) माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लागू नवाचार **''उन्नयन बाँका''** की सफलता को देखते हुए बिहार के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में सूचना टेक्नोलॉजी का उपयोग कर शैक्षणिक वातावरण में सुधार की कार्रवाई के उदेश्य से **''उन्नयन बिहार''** अगस्त, 2019 से प्रारंभ किया जा रहा है।

(5) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत वितीय वर्ष 2018-19 में कुल 43,336 (तेतालीस हजार तीन सौ छत्तीस) विद्यार्थियों को उच्चत्तर शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया है। इसके तहत ₹1157.24 करोड़ (एक हजार एक सौ संतावन करोड़ चौबीस लाख रूपये) स्वीकृत राशि से 34,999 (चौतीस हजार नौ सौ निन्यानवे) छात्र-छात्राओं को ₹307.43 करोड़ (तीन सौ सात करोड़ तेतालीस हजार रूपये) वितरित किया जा चुका है।

(6) बिहार के चतुर्दिक विकास में शिक्षा को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। हमारी आर्थिक उन्नति, सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नैतिक बल और चरित्र, शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन काल से ही शिक्षा के मामले में बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार सभी वर्गो के लिए खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के बच्चों- बच्चियों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है। इसमें हमें सफलता भी मिली है।

(7) बिहार में 99% से अधिक बच्चे विद्यालय में नामांकित हो गये हैं। शेष 1% से कम विद्यालय के बाहर के बच्चों को विद्यालय में लाने का कार्य चल रहा है। विद्यालयों के अनुश्रवण हेतु बेस्ट (Bihar Easy School Tracking) नामक एक मोबाईल एप विकसित किया गया है। इस एप के द्वारा कुल 45,628 (पैतालीस हजार छः सौ अठाईस) प्रारंभिक विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है एवं इस निरीक्षण से शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति में सुधार हुआ है।

(8) प्राथमिक,माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पद पर नियोजन की कार्रवाई माह जुलाई, 2019 से प्रारंभ करते हुए फरवरी, 2020 तक विभिन्न चरणों में पूर्ण करने के लिए हम काम कर रहे है।

(9) मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना मद से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10 वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के 39,023 (उनचालीस हजार तेइस) छात्राओं के लिए प्रति छात्रा ₹10,000/-(दस हजार रूपये) की दर से राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

(10) मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2018 में उत्तीर्णता प्राप्त सभी कोटि के अविवाहित छात्राओं को प्रति छात्रा ₹10,000 (दस हजार रूपये) की दर से कुल 2,49,856 (दो लाख उनचास हजार आठ सौ छप्पन) छात्राओं के लिए ₹249.86 करोड़ (दो सौ उनचास करोड़ छियासी लाख रूपये) उपलब्ध कराया गया है।

(11) बालिका शिक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाये गए। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना, पोशाक योजना, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम (सैनिटरी नैपकिन) इनमें महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साईकिल योजना,छात्रवृति योजना पूर्व से संचालित है। फलतः बिहार में बालिका शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2019 की मैट्रिक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में बालिकाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है। आज माध्यमिक स्तर तक बालक एवं बालिका शिक्षा में अन्तर (Gap) शून्य है।

(12) उक्त सभी बालिका से संबंधित योजनाओं का उदेश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, कुल प्रजनन दर में कमी लाना तथा लिंग अनुपात के असमानता को समाप्त करना है। इन सभी उदेश्यों के प्राप्ति में हम कमशः तेजी से आगे बढ़ रहे है। शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया। फलतः पूर्व में जहाँ मात्र 19% महिलायें शिक्षिका थीं, बढ़कर अब 39% हो गयी हैं।

(13) वर्ष 2019 के माध्यमिक परीक्षा में 8,22,842 (आठ लाख बाईस हजार आठ सौ बियालीस) छात्र एंव 8,37,767(आठ लाख सैंतीस हजार सात सौ सड़सठ) छात्राओं ने भाग लिया। स्पष्टतः छात्राओं में शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ी है। मैट्रिक में 77.58% छात्र एवं 79.80% छात्राओं ने उत्तीर्णता हासिल की है। इन्टरमीडिएट में 83.19% छात्र तथा 76.01% छात्राओं ने उत्तीर्णता हासिल की है। आधी आबादी अपने अधिकारों के प्रति जागरुक एवं सतत् प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हैं।

(14) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था में किये गए महत्वपूर्ण तकनीकी बदलावों के परिणामस्वरूप समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं माध्यमिक वार्षिक परीक्षा, 2019 का परीक्षाफल मूल्यांकन प्रारम्भ होने की तिथि से मात्र 28 दिनों के अंदर प्रकाशित किया गया, जो पूरे देश में एक कीर्तिमान है।

(15) राज्य सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के संचालन की अधिसूचना निर्गत की गई और यह संस्था संचालित हो चुकी है।

(16) राज्य सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालय के अलावा 07 निजी विश्वविद्यालयों यथा– अमिटी विश्वविद्यालय पटना, संदीप विश्वविद्यालय मधुबनी, के० के० विश्वविद्यालय नालन्दा, डॉ सी०वी० रमण विश्वविद्यालय, वैशाली, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार (सासाराम), अल–करीम विश्वविद्यालय, कटिहार एवं माता गुजरी विश्वविद्यालय, किशनगंज की स्थापना की गई है।

(17) तकनीकी शिक्षा के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विशवविद्यालय की स्थापना की गई है। इसमें नैनो सायंस एवं नैनो टेक्नॉलौजी के अध्ययन की व्यवस्था है तथा "School of Journalism and Mass Communication", "Patliputra School of Economics" and "Centre for River Studies" एवं "Centre for Geographical Studies" के रूप में चार स्वायत्तशासी उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना की गई है। इस प्रकार बिहार के शैक्षणिक जगत में ठोस और परिणामकारी कार्य करने में हम अग्रसर हैं।

(18) गांधीजी के जीवन पर आधारित शिक्षाप्रद कहानियों की दो किताबें ''एक था मोहन'' एवं ''बापू की पाती'' तैयार की गई हैं। प्रतिदिन प्रार्थना के बाद उनमें से एक कहानी पढ़ी जा रही है। इसकी व्यापक सराहना हो रही है। शिक्षक, छात्र सभी इसमें रुचि ले रहे हैं।

(19) **शिक्षा पर व्यय**

(i) शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के व्यय वहन हेतु कुल ₹347,98,69,44,000 (तीन सौ सैतालिस अरब अन्ठानवे करोड़ उन्हत्तर लाख चौवालिस हजार रूपये) का उपबंध मांग संख्या-21 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अलावे राज्य स्कीम एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीम शामिल हैं।

(ii) इस में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए ₹144,89,66,44,000 (एक सौ चौवालिस अरब नवासी करोड़ छियासठ लाख चौवालिस हजार रुपये) प्रस्तावित है।

(iii) वार्षिक स्कीम के लिए कुल ₹203,09,03,00,000 (दो सौ तीन अरब नौ करोड़ तीन लाख रूपये) का प्रस्तावित है, जिसमें से केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि ₹82,14,03,00,000 (बेरासी अरब चौदह करोड़ तीन लाख रूपये), राज्यांश की राशि ₹87,24,90,24,000(सतासी अरब चौबीस करोड़ नब्बे लाख चौबीस हजार रूपये), राज्य स्कीम के लिए ₹32,20,09,76,000 (बत्तीस अरब बीस करोड़ नौ लाख छिहत्तर हजार रूपये) एवं वाह्य सम्पोषित परियोजना हेतु ₹1,50,00,00,000 (एक अरब पचास करोड़ रूपये) का बजट प्रस्तावित है।